स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–25, अंक–8

श्रावण–भाद्रपद 2074, अगस्त 2017

संपादक

अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–6

सरकार भी रोक सकती है चीनी आयात

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **आवरण कथा**
चीनी वस्तुओं से मोह भंग जरूरी
.... भरत झुनझुनवाला

10 **आवरण कथा**
महंगा पड़ेगा चीन को डोकलाम
.... दुलीचन्द रमन

12 **ज्वलंत मुद्दा**
गंभीर संकट में चीन – ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार
.... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

17 **विचार**
विदेशी प्रभाव से मुक्त हो नीति–निर्माण
.... राजीव कुमार

19 **समीक्षा**
कर्जमाफी से अलग भी सोचें
.... देविंदर शर्मा

21 **जीएम फसलें**
सरसों की जीएम फसल से जुड़े व्यापक सवाल
.... भारत डोगरा

23 **आकलन**
ग्रामीण विकास का दौर
.... अनिल तिवारी

26 **शिक्षा**
सुधार की राह देखती देश की शिक्षा व्यवस्था
.... आशीष रावत

28 **शिक्षा**
वर्तमान शिक्षण में रचनात्मकता आवश्यक
.... डॉ. रेखा भट्ट

31 **आयुर्वेद**
पथ्य पालन से रोग का स्वयं ही निवारण हो जाता है...
.... वैद्या हेतल दवे

34 **रपट**
जिला सम्मेलन, फरीदाबाद (हरियाणा)

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 36-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

पाठकनामा

जीएम फसलों से पर्यावरण व जीवन को खतरा

महोदय, सम्मानित मासिक 'स्वदेशी पत्रिका' का जुलाई 2017 अंक, जोकि किसानों पर केंद्रित था, देखने को मिला। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद देश के अन्य वर्गों के साथ–साथ किसानों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को लेकर पत्रिका द्वारा किया गया आकलन न सिर्फ उपयोगी है, बल्कि शिक्षार्थियों, शोधार्थियों के लिए भी बहुत लाभप्रद है।

डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा लिखित आवरण कथा 'किसानों को समृद्व बनाइए' विषयक आलेख में वर्तमान का कृषि संकट उत्पादन में कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण ही केवल नहीं है। उनका यह कहना कि वर्तमान कृषि संकट के पीछे नीति–निर्माताओं का भी कुछ दोष है, जिसे वे न तो स्वीकार कर रहे है और न ही मामले की तह में जाकर इस संकट का कोई स्थायी समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेख में कहा है कि कर्ज माफी कोई रास्ता नहीं है। इस कर्ज माफी की खैरात से कृषि का स्वास्थ्य सही होने वाला नहीं है। बल्कि कृषि उपज का वाजिब मूल्य किसानों को दिलवाकर इस समस्या का बहुत हद तक समाधान किया जा सकता है। इस क्रम में आशीष रावत की शिकायत कि 'किसानों के साथ अन्याय क्यूं' अच्छा संकलन है। रावत ने प्रकांड पंडित कौटिल्य को कोट करते हुए कहा भी है कि राजा को अपने राज्य में कृषि को बढ़ाने और कृषि कार्य में संलग्न लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह एक आदर्श स्थिति है। बताते हैं कि प्राचीन काल में भारत की कृषि व्यवस्था सुदृढ़ इसलिए ही थी, क्योंकि तत्कालीन शासकों के प्राथमिकता कृषि थी।

डॉ. भरत झुनझुनवाला व डॉ. देविंदर शर्मा का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर अलग दृष्टि प्रदान करती है। वहीं प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा का चीन से दो–चार करने व भरत डोबरा का जीएम फसलों को लेकर की गई चिंता भी महत्वपूर्ण है।

देवेन्द्र त्रिपाठी, *इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)*

✽✽✽✽✽

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

ट्वीट्स

हमारे त्यौहार, उत्सव एक सामाजिक सुधार का अभियान है। हमारे ये सभी त्यौहार गरीबों की आर्थिक जिंदगी के साथ सीधा संबंध रखते हैं।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

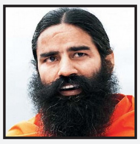

चीन ने हमेशा हमें धोखा दिया है, चीनी उत्पाद खरीदना, दुश्मन की मदद करना है। हर राष्ट्रवादी भारतीयों को चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए।

बाबा रामदेव

पूंजीवाद व उदारवाद के नाम से चल रही धारा का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रो. पनगढ़िया।

अरूण ओझा
राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

यदि मेरी उम्र 40 वर्ष होती, तो मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाती.. इस उम्र में कोलंबिया में मेरे लिए नौकरी मिलना लगभग असंभव है।

अरविंद पनगढ़िया
(नीति आयोग से इस्तीफा देते समय)

सं
पा
द
की
य

कैसा हो नीति आयोग?

कुछ दिन पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. अरविंद पनगरिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र सौंप दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी छुट्‌टी को और आगे बढ़ाने से विश्वविद्यालय ने मना कर दिया है, इसलिए उन्हें वापिस जाना जरूरी है। उसके बाद सरकार द्वारा उनके स्थान पर डॉ. राजीव कुमार, अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल विशेषज्ञ डॉ. विनोद पॉल को एक अन्य सदस्य के नाते भी नियुक्त किया गया है।

नीति आयोग जनवरी 1, 2015 को आस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि पूर्व से चल रहे योजना आयोग को बदलकर एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। नीति (नेशनल इंस्टीट्‌यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया) आयोग के गठन के समय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्हें अनुभव आया था कि देश में राज्यों को हमेशा केन्द्र से मांगते रहने के लिए मजबूर किया जाता है। केन्द्र से योजनाएं बनती हैं और उसे कई बार न चाहते हुए भी राज्यों को उन्हें लागू करना पड़ता है। ऐसे में देश में कॉओपरेटिव फेडेरलिज्म (सहकार के साथ संघवाद) अपनाने की जरूरत है। 'वन साईज फिट ऑल' की अवधारणा सही नहीं है। ऊपर से योजना बनकर नीचे तक जाए, उसके बजाय जरूरी है कि नीचे से योजना बने और वही ऊपर से अनुमोदित हो।

नीति आयोग राज्यों के सशक्तिकरण का भी प्रतीक था। पूर्व के योजना आयोग के पास जो राज्यों की योजना हेतु राशि के आवंटन का अधिकार था, वह अधिकार नीति आयोग के पास नहीं था। नीति आयोग के बारे में कहा गया कि वह 'शक्ति केन्द्र' की बजाय एक 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करेगा। नीति आयोग के गठन के बाद यह स्वभाविक अपेक्षा थी कि जीडीपी ग्रोथ के साथ–साथ देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि की समस्या के निराकरण के लिए राज्यों के साथ मिल–बैठ कर ऐसी नीतियां बनेंगी, जिसमें समस्याओं का निराकरण सहकार के आधार पर होगा। गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने अथवा शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाकर आमजन के जीवन स्तर में सुधार हेतु उपाय सुझाने की बजाय नीति आयोग का ध्यान केवल उन मुद्‌दों पर अधिक रहा जिससे कारपोरेट जगत और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंच सकता था। विवादित जीएम फसलों को अनुमति दिए जाने की सिफारिश से लेकर दवाईयों को सस्ते होने के लिए स्थापित एनपीपीए की व्यवस्था को ही भंग करने की सिफारिश समेत कई उदाहरण हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नीति आयोग कारपोरेट हितों को बढ़ावा देने में ज्यादा विश्वास रखता रहा है। यही नहीं घोषित रूप से कारपोरेट हितों की संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्मों की भी सेवाएं लेने से नीति आयोग ने परहेज नहीं किया।

जरूरी है कि योजना आयोग में बैठे वे सभी लोग कारपोरेट के प्रभाव से अलग किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों, वंचितों आदि का मर्म समझते हों। ऐसे में यह बताना उचित होगा कि दुनिया में विकास के बारे दो प्रकार की सोच विद्यमान हैं। एक प्रकार की सोच प्रो. जगदीश भगवती और अरविन्द पनगरिया जी की है जो यह कहती है कि हमें केवल जीडीपी की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी तो उसके लाभ अपनेआप गरीबों और वंचितों तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए उनका कहना है कि इस ग्रोथ को लाने में भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार ही एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर एक अन्य सोच है जिसका प्रतिनिधित्व अमर्त्य सेन करते हैं। अमर्त्य सेन का कहना है कि भूमंडलीकरण, मुक्त व्यापार सबके साथ–साथ जो असमानताएं बढ़ जाती हैं, और जिससे गरीबों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है, ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए गरीबों को खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार गारंटी (जैसे नरेगा) आदि उपलब्ध कराकर उनके संकट को कम कर सकते हैं। इन दोनों सोचों से अलग एक तीसरी सोच है जिसे तीसरा रास्ता या तीसरा विकल्प कहा जा सकता है। वह यह है कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था बने जिसमें लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिसमें किसान को उसकी उपज का उपयुक्त मूल्य मिले, जिसमें कारपोरेट प्रभाव को दरकिनार करते हुए लघु व्यवसायों को बढ़ावा मिले। एक ऐसी सोच जिसमें केवल जीडीपी ग्रोथ की बात न हो, बल्कि जिसमें रोजगार सृजन निहित हो। कोई भी नीति जो रोजगारहीन विकास करती हो, उसे बदलकर एक ऐसी नीतियों का निर्माण हो जिसमें सभी को कमाने के पूरे अवसर मिले, ताकि उनको भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि के लिए सरकार के सामने भी हाथ न फैलाने पड़े। ❑

सरकार भी रोक सकती है चीनी आयात

अभी तक 93 चीनी वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा चुकी है और 40 मामलों में कार्यवाही चल रही है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यंत असंतुलित है। गौरतलब है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016–17 में भारत से 276.3 अरब डालर के निर्यात हुए, जबकि आयात 384.3 अरब डालर के थे। यानि भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा 108 अरब डालर का था। हालांकि पिछले दो–तीन सालों में पहले की अपेक्षा भारत का कुल व्यापार घाटा काफी कम हुआ है, लेकिन साथ ही साथ चीन से व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन से कुल व्यापार 71.5 अरब डालर होने पर, 51.1 अरब डालर, वास्तव में चिंता का विषय है। गौरतलब है कि चीन से व्यापार घाटा हमारे कुल घाटे का 47.3 प्रतिशत है। हमारी वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भी इस बड़े व्यापार घाटे के प्रति चिंता व्यक्त की जाती रही है। चीन के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका, ईरान, रूस, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जिनके साथ व्यापार घाटा हाल ही में बढ़ गया है।

व्यापार घाटा कम करने का एक तरीका यह है कि चीन को अपने निर्यात बढ़ाए जाएं और दूसरा यह कि चीन से आयात कम किए जाएं। जहां तक निर्यात बढ़ाने का प्रश्न है, आज भारत चीन को कच्चा लोहा, अन्य प्रकार की धातुओं और कुछ कृषि वस्तुओं आदि का निर्यात करता है। हालांकि वर्ष 2016–17 में चीन को होने वाले निर्यातों में मामूली सी (1.2 अरब डालर) की वृद्धि हुई है। लेकिन चीन से व्यापार घाटा पाटने के लिए वह कतई पर्याप्त नहीं है।

चीन को निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं नगण्य हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन से आयात घटाने की अपार संभावनाएं हैं। कई बार कच्चे तेल आदि ऐसे आयात होते हैं, जिनका देश में कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन चीन से आने वाले आयातों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। चीन से तमाम प्रकार के आयातों में से अधिकांश ऐसे हैं, जिनका देश में उत्पादन होता है। ऐसा भी हुआ है कि चीन द्वारा सस्ते सामान की 'डंपिंग' करने से भारतीय उद्योग नष्ट हो गए हैं। कोई देश जब अपनी लागत से भी कम कीमत पर माल बेचता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। ऐसा करने के लिए चीन की सरकार अपने निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करती है। लागत

से भी सस्ता माल आयात होने के कारण भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाता और उद्योग नष्ट होते जा रहे हैं।

डब्ल्यूटीओ समझौतों में यह प्रावधान है कि यदि कोई देश लागत से कम कीमत पर निर्यात करता है और हमारे देश के उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसे आयातों पर एंटी–डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है।

क्या है एंटी डंपिंग की प्रक्रिया?

जब कोई देश सामान्य से कम मूल्य पर अपना सामान किसी देश में बेचता है और उससे घरेलू उत्पादकों पर गलत असर पड़ता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। ऐसा तय करने के लिए मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि वह वस्तु निर्यातक देश के घरेलू बाजार में किस कीमत पर बेची जा रही है और किस मूल्य पर वह निर्यात की जा रही है। अगर निर्यात का मूल्य घरेलू मूल्य से कम है तो उसे डंपिंग कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में आयातक देश की सरकार के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके लिए पारदर्शिता के साथ पूरी जांच होती है और निर्यातक देश के संबंधित पक्षों को अपने हितों के संरक्षण के लिए पूरा अवसर भी दिया जाता है। राज्यसभा में भारत की वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि जुलाई 17, 2017 तक कुल 141 मामलों में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा चुकी है। इसमें से 93 एंटी डंपिंग ड्यूटी के मामले चीन से संबंधित हैं और कुल 54 और मामलों में एंटी डंपिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 40 चीन से संबंधित हैं।

क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का असर?

एंटी ड्यूटी लगाने से देश में गलत तरीके से सस्ता माल आने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है, जिससे उन वस्तुओं का आयात कम होने लगता है। पिछले वर्ष जब लोहा इस्पात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई उसके चलते लोहा इस्पात का आयात वर्ष 2016–17 में 43 प्रतिशत कम हो गया। गौरतलब है कि रसायनों, कांच और कांच के सामान और दवाओं पर इनकी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते आगे चलकर इन वस्तुओं का आयात कम होने वाला है। वर्ष 2016–17 में उर्वरकों का आयात 62 प्रतिशत कम हुआ है, इसके पीछे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी ही कारण है। उर्वरकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को अभी और भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे उर्वरकों का आयात और भी कम होगा। जिन मामलों में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है आगे चलकर उनका आयात भी घटेगा क्योंकि घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयातों की तुलना में संरक्षण मिल पाएगा। हालांकि कुछ मामलों में चीन से आयात घटे हैं, लेकिन यह भी सही है कि कई मामलों में चीन से आयात बढ़े भी हैं। कांच और कांच के उत्पादों का आयात पिछले साल 17 प्रतिशत बढ़ा, रसायनिक उत्पादों का आयात 34 प्रतिशत बढ़ा, इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक्स का आयात 11 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा जबकि जलपोत, नौका इत्यादि का आयात 15 प्रतिशत बढ़ गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से रसायन, कांच और कांच के सामान और दवा इत्यादि का आयात निश्चित रूप से घटेगा।

भारत सरकार के पास और भी हैं तरीके

आमतौर पर बहिष्कार का समर्थन नहीं कर रहे लोगों का यह तर्क रहता है कि चूंकि हम डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत व्यापार समझौतों से बंधे हुए हैं, हम चीनी माल पर टैरिफ या गैर टैरिफ बाधाएं लगाकर उसे रोक नहीं सकते। हालांकि यह सही है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई सरकार विदेशों से आने वाले आयातों पर अनावश्यक टैरिफ लगाकर या अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाकर उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी संप्रभु सरकार विदेशी माल को सरकारी खरीद से बाहर कर सकती है। बाय अमेरिकन एक्ट 1933 के अनुसार अमरीकी सरकार अपनी खरीद में सिर्फ अमरीकी सामान खरीदने की अधिकार रखती है। इसी तर्ज पर हाल ही में भारत सरकार ने नियमों में बदलाव कर जनरल फाइनेसिएल रूल्स की उपधारा 153 के अनुसार यह निर्देशित किया है कि सरकारी खरीद में देश का बना हुआ सामान ही खरीदा जाए। इसके अंतर्गत 50 लाख रूपए तक की सरकारी खरीद में सिर्फ देश का बना हुआ सामान ही खरीदा जाएगा और 50 लाख से अधिक की खरीद में 20 प्रतिशत मार्जिन के साथ भारतीय सामान खरीदा जा सकेगा, यानि भारतीय सामान 20 प्रतिशत महंगा होने पर भी खरीदा जा सकेगा।

इसके अलावा यह कहना पूरा सही नहीं है कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत हमें हर सामान को खरीदना अनिवार्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि चीनी सामान सस्ता ही नहीं बल्कि घटिया किस्म का होता है। इसलिए उसे रोकने के लिए हमें मात्र मानक तय करने हैं। यदि वह सामान हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरता है, हम उसे तुरंत रोक सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार चीन से आने वाले सामानों के मानक तय कर उन्हें घोषित करे। भारत सरकार ने अभी तक प्लास्टिक के सामान, पावर प्लांटों इत्यादि पर मानक लगाकर चीनी आयातों को आने से रोका भी है। भारत सरकार के सभी विभागों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे अपने अंतर्गत आने वाले विषयों से संबद्ध उत्पादों के लिए मानक तय करें और उन मानकों पर सही न उतरने वाले उत्पादों से आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ❑❑

चीनी वस्तुओं से मोह भंग जरूरी

सीमा पर चीन के अड़ियल रवैये को देखते हुए देश में मांग उठ रही है कि चीनी माल का बहिष्कार किया जाए। बात सही है। परंतु प्रश्न है कि चीन के माल की यह घुसपैठ हो कैसे रही है? भारत और चीन दोनों एक ही विश्व बाजार में स्थित है। जैसे एक ही मंडी में आलू बेचने वाले दो व्यापारी स्थित होते है, वैसे ही हम और चीन विश्व बाजार में हैं। हमारे दोनों देशों को विश्व बाजार से एक ही दाम पर कच्चा माल खरीदना होता है जैसे तेल, कोयला एवं लौह खनिज। तब चीन का माल सस्ता और भारत का माल मंहगा क्यों पड़ता है? मंडी में एक व्यापारी चीन से आयातित सस्ता आलू बेच रहा है और दूसरा भारत में उत्पादित मंहगा आलू बेच रहा है। अब हमारे विचारक कह रहे है कि चीन के सस्ते आलू का बहिष्कार किया जाए। यह क्यों नही सोचते कि भारत में उत्पादित आलू की लागत ज्यादा क्यों आ रही है?

भारत में लागत ज्यादा आने का मूल कारण भ्रष्टाचार है जो कि बुनियादी संरचना के खस्ता हाल में भी दिखता है। भ्रष्टाचार सीधे किसान अथवा उद्यमी को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे भ्रष्टाचार के कारण नहर की मरम्मत नहीं होती है, पानी का रिसाव होता है और किसान को नहर का सस्ता पानी नहीं मिलता है। बिजली विभाग में चोरी के कारण बड़ी मछलियों को बिजली सस्ती मिलती है और बिजली बोर्ड को घाटा लगता है जिसके कारण बोर्ड द्वारा बिजली के दाम बढ़ाए जाते है। बिजली लाइनों की रिपेयर का माल ब्लैक में बेच दिया जाता है और उद्यमी को बिजली नही मिलती है। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार के कारण लेबर इंसपेक्टर, फैक्ट्री इंसपेक्टर, वेट्स एंड मेजर्स इंसपेक्टर आदि को घूस देनी पड़ती है। इन कारणों से भारत में उत्पादन लागत ज्यादा आती है और चीन का माल घुसपैठ करने में सफल होता है। लेकिन भारतीय किसान को टेलीविजन तथा बाइक चाहिए। खेती में घाटा लग रहा है परंतु खपत बढ़ाने की ललक है। भारत सरकार द्वारा ''विकास'' का नारा देकर खपत बढ़ाने को देशवासियों को प्रेरित किया जा रहा है। सपना परोसा जा रहा है

मैं चीन के माल का बहिष्कार करने का समर्थन करता हूं। परंतु पहले हमें अपनी दुर्नीतियों को ठीक करना होगा। अपनी नौकरशाही को व्यापार सुलभ बनाने की ओर मोड़ना होगा। देश के सामने दुनिया खरीदने का सपना परोसना होगा।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

कि शीघ्र ही हमारे देशवासी अमरीका की तर्ज पर खपत करेंगे। फलस्वरूप किसान या तो अपनी जमीन बेचता है अथवा शहर में काम कर रहे बेटे द्वारा भेजी गई रकम से बाइक खरीदता है। अपना धंधा घाटे में और दूसरी आय से लाइफ को इंज्याय किया जा रहा है। यही प्रक्रिया हम देश के स्तर पर अपना रहे है। हमारी उत्पादन लागत ज्यादा आ रही है। हमारे निर्यात कम एवं आयात ज्यादा है। हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ''विकास'' की आस में हम फ्लैट स्क्रीन टीवी तथा एन्ड्रायड मोबाइल फोन खरीदना चाहते है। हमारी अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है परंतु हम अपने बेटी–बेटों द्वारा भेजी गई रकम का उपयोग खपत बढ़ाने में कर रहे है।

अब सवाल है कि चीन का माल सस्ता क्यों है? जानकार बताते है कि चीन की सरकार उद्यमी तथा व्यापारी को हर तरह से सहायता करती है। चीन से माल का आयात करने वाले एक भारतीय व्यापारी ने उदाहरण दिया कि वहाँ एक स्कीम के अंतर्गत पूरे एक कंटेनर माल के निर्यात का एक बिल बनाने पर टैक्स में 5 से 7 प्रतिशत रिबेट मिलता है। रिबेट लेने के लिए घूस नहीं देनी होती है। दस बार सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने होते है। बिल जमा करने पर रिबेट की रकम तत्काल खाते में आ जाती है। जानकार यह भी बताते है वहां भी भ्रष्टाचार व्याप्त है–परंतु यह ऊंचे स्तर पर है और इसका रूप व्यापार को बढ़ावा देने का है। जैसे उद्यमी जमीन खरीदना चाहता है तो घूस लेकर उसे सस्ती जमीन उपलब्ध करा दी जाती है। एक लाख की जमीन को चीन में घूस लेकर 50 हजार में उपलब्ध कराया जाता है। हमारे नौकरशाह भी घूस वसूल करते है और एक लाख की जमीन की खरीद में अडंगा लगाकर डेढ़ लाख मे उद्यमी को वह जमीन मिलती है।

चीन का माल सस्ता होने का दूसरा कारण चीन पर्यावरण की क्षति करने की छूट है। वहां भूमिगत पानी और हवा दोनों प्रदूषित हो चले है। लोगों का स्वास्थ गिर रहा है। भारत में अब तक पर्यावरण को नष्ट करने की तुलना में छूट कम थी। वर्तमान सरकार चीन की इस दूर्नीति को अपनाने की तरफ बढ़ रही है। जंगल को काटना आसान बना दिया गया है। गंगा पर जलविद्युत परियोजनाएं बनाकर उसे नष्ट किया जा रहा है।

नौकरशाही के व्यापार के प्रति सकारात्मक भ्रष्टाचार तथा पर्यावरण की क्षति की छूट के कारण चीन का माल बाजार में सस्ता पड़ता है। यूँ समझिए कि अपने पानी और हवा का निर्यात करके चीन धन कमा रहा है। इस धन का उपयोग वह दुनिया को खरीदने में कर रहा है। चीन की सरकार ने भारी मात्रा में अमरीका सरकार द्वारा जारी बांड खरीद रखे है और अमरीका को दबाव में ले लिया है। चीन की कंपनियां पूरी दुनिया में विचरण करके जमीन तथा शीर्ष कंपनियों को खरीद रही है। इसलिए चीन का दुनिया में दबदबा है।

चीन का माल सस्ता होने का दूसरा कारण चीन में पर्यावरण की क्षति करने की छूट है। वहां भूमिगत पानी और हवा दोनों प्रदूषित हो चले है।

अब भारत तथा चीन के माडल के अंतर को समझा जा सकता है। पहला अंतर है कि भारत की नौकरशाही व्यापार में ब्रेक लगाकर घूस वसूल करती है जबकि चीन की नौकरशाही व्यापार में मोबिल आयल डालकर घूस वसूल करती है। साथ–साथ भारत में प्रदूषण फैलाने की फिलहाल छूट कम है। इन कारण भारत में उत्पादन लागत ज्यादा आती है और चीन में कम। दूसरा अंतर है कि निर्यात से कमाई गई रकम का उपयोग चीन की सरकार तथा उद्यमियों द्वारा दुनिया को खरीदने में किया जा रहा है। तुलना में हम अपने बेटे बेटियों द्वारा भेजी गई रकम का उपयोग एन्ड्रायड फोन खरीदने एवं लाईफ को इंजाय करने में कर रहे है। साथ–साथ हम गुहार लगा रहे है कि चीन के सस्ते माल का बहिष्कार करना चाहिए। हम अपनी दुर्नीतियों को ठीक नही करना चाहते है। अपने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नही करना चाहते है। एन्ड्रायड फोन खरीदने की ललक को दबाना नही चाहते है।

चीन से हम गलत सबक लेने को उतारू है। चीन की तर्ज पर पर्यावरण को हम नष्ट करने की ओर बढ़ रहे है। चीन की तरह व्यापार को बढ़ावा देने की सीख लेने को हम तैयार नहीं है। डिजिटल इंडिया तथा जीएसटी से हम व्यापार को जटिल बनाते जा रहे है। चीन के नागरिक और सरकार रकम का उपयोग दुनिया को खरीदने में कर रहे है। हम इस मंत्र को उनसे नही सीखना चाहते है। उलटे ऐसा जता रहे है कि चीन भारत में सस्ता माल बेचकर कुछ गलत कर रहा है जिसके लिए उसके माल का बहिष्कार करना चाहिए।

मैं चीन के माल का बहिष्कार करने का समर्थन करता हूं। परंतु पहले हमें अपनी दुर्नीतियों को ठीक करना होगा। अपनी नौकरशाही को व्यापार को सुलभ बनाने की ओर मोड़ना होगा। देश के सामने दुनिया खरीदने का सपना परोसना होगा। अपनी नौकरशाही के भ्रष्टाचार और अपने देशवासियों को उत्तरोत्तर खपत के मंत्रों को पढ़ाकर चीन के माल का बहिष्कार न तो लागू हो पाएगा, न ही सफल होगा। ❑❑

महंगा पड़ेगा चीन को डोकलाम

क्या है वर्तमान मुद्दा

भारत–भूटान और चीन की सीमा पर स्थित चुम्बी घाटी के पठार डोकलाम में पिछले 16 जून से भारत और चीन की सेना में आमने–सामने जमी है। हल्की झड़पो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं। बात दरअसल जून के प्रथम सप्ताह में शुरू हुई थी, जब चीनी सेना ने भूटानी सेना के दो बंकरों को बुल्डोजर की मदद से ढ़हा दिया और उस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य करना आरंभ कर दिया। डोकलाम में अभी तक भारत–चीन– भूटान के बीच सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है। 2012 की संधि के अनुसार कोई भी एक देश सीमा निर्धारण का कार्य एकपक्षीय नहीं कर सकता। चीन इस क्षेत्र में निर्माण कर इस संधि का उल्लघंन कर रहा है।

भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी के बीच सीमा पर स्थित नाथूला दर्रे से होकर जाने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भी चीन ने रोक दिया। वर्तमान में दोनों सेनायें अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है।

डोकलाम का क्षेत्र भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वहां चीन की उपस्थिति भारत की सुरक्षा व अखंड़ता के लिए खतरा बन सकती है। डोकलाम का क्षेत्र "सिलिगुड़ी–गलियारे" से ज्यादा दूर नहीं है जो उत्तर–पूर्व के राज्यों को भारतीय मुख्य भू–भाग से जोड़ता है। जिसे मीडिया की भाषा में 'चिकन नेक' भी कहा जाता है। डोकलाम का क्षेत्र सैन्य दृष्टि से भी भारत के पक्ष में है इसके एक तरफ सिक्किम में भारतीय सेनायें तैनात है तो दूसरी तरफ भूटान में भूटानी शाही सेना के प्रशिक्षण के लिए 'हां' में स्थित भारतीय सेना की 'IMTRAT' बिग्रेड। इन दोनों के बीच चीन कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। किसी भी युद्व या टकराव की स्थिति में भारतीय सेनायें चीनी सेनाओं पर दोतरफा वार कर चीनी सेना का आपूर्ति मार्ग बंद कर सकती है। चीन इस स्थिति को भांपकर वहां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण का कार्य करना चाहता है और यही वर्तमान संघर्ष की जड़ है।

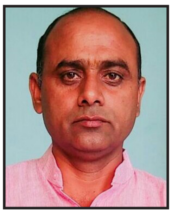

29 अक्टूबर 2017 को दिल्ली के रामलीला मैदान में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा होने वाली प्रदर्शन रैली चीन के भारतीय बाज़ार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जिसकी गूँज विश्वभर में सुनाई देगी। डोकलाम चीन के लिए सचमुच बहुत मंहगा पड़ने वाला है।

– **दुलीचन्द रमन**

डोकलाम के बहाने आखिर चीन चाहता क्या है?

चीन की रणनीति अपने पड़ोसी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रही है। भारत और भूटान के साथ भी वह यही खेल, खेल रहा है। पिछले करीब दो सालों के चीनी रिश्तों पर नज़र डाले तो उसकी इस मंशा को समझा जा सकता है। मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतराष्ट्रीय आंतकवादी घोषित करवाने की भारत की कोशिशों के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करना, भारत की "परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह" में सदस्यता में रोडा अटकाना, दलाईलामा की अरूणाचल प्रदेश की यात्रा का विरोध करना, नत्थी वीजा का मामला हो या भारत का ताईवान के साथ मिलकर दक्षिणी चीन सागर में तेल उत्खनन का विरोध।

चीन ने भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों पर निवेश के नाम पर डोरे डालकर अपने

प्रभाव में लेने की कोशिश की है। वह कुछ हद तक सफल भी हुआ है। उसने बंगलादेश के चिटगांव बंदरगाह, म्यांमार के कोको द्वीप पर, श्रीलंका की हब्बबटोटा बदंरगाह तथा पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अपनी सैनिक गतिविधियाँ भारतीय जल क्षेत्र के आस–पास बढ़ा दी है। नेपाल में वह माओवाद के नाम पर वहां के सत्ता प्रतिष्ठान को अपना हितैषी बना चुका है।

चीन के साथ भूटान के राजनीतिक संबंध नहीं है। भूटान की विदेश नीति, रक्षा और कुछ हद तक अर्थव्यवस्था भी भारत की जिम्मेदारी है। शायद इसी कारण वह भूटान के बहाने भारत के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। भारत के पिछले दिनों चीन की महत्त्वकांक्षी (OBOR) ओबोर परियोजना के अतंर्गत पाकिस्तान आधिकृत कश्मीर से होकर बनने वाले "चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे" का विरोध किया था। चीन की अर्थव्यवस्था मुख्यता निर्यात आधारित है। निर्यात बढ़ाने के लिए ओबोर परियोजना को सफल बनाना चीन के लिए चुनौती बन चुका है। चीन की आर्थिक विकास दर लगातार कम हो रही है तथा ऋण बढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहे चीन को ओबोर परियोजना आशा की आखिरी किरण नज़र आ रही है।

ओबोर के जवाब में भारत ने दक्षिण एशिया के देशों जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार को सड़क मार्ग से जोड़कर एक आर्थिक गलियारे की व्यूह रचना प्रांरभ कर दी है। चीन को डर है कि कहीं उसके अन्य पड़ोसी देश जिनसे चीन के अच्छे रिश्ते नहीं है वे भारत की अगुवाई में लाभबंद्व न हो जाये। इसी कारण चीन कभी कश्मीर में भारत–पाक के बीच मध्यस्थता का सपना देखता है तो कभी सिक्किम के भारत में विलय के इतिहास को पलटना चाहता है।

चीनी अतिउत्साह के कारण

भारत की पूर्व की सरकारों ने चीन के प्रति सदा ही नर्मी दिखाई है। "हिन्दी चीनी–भाई भाई" से लेकर 'पंचशील' के ढकोसलों और ख्याली पुलावों को हमेशा चीन ने तोड़ा है। चीनी सीमा पर लगातार बढ़ती घुसपैठ और अतिक्रमण के सामने हमेशा ही आत्मसमर्पण किया गया तथा चीनी सरकार की अनुचित मांगों को मानकर सीमा पर शांति के नाम पर सुरक्षा बलों को पीछे हटने को मजबूर किया गया। भारतीय विदेश नीति के कर्णधारों ने हमेशा ही पश्चिम के देशों को तरजीह दी तथा हमारे पूर्व के देशों को नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक इसी समय चीन आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था तथा उसने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। "लुक ईस्ट पालिसी" के नाम पर इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापूर, ब्रुनेई के साथ विदेश संबंधों को तव्वजों देने की कोशिश की गई, मगर तब तक बह्मपुत्र में काफी पानी बह चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति संभालने की कोशिश में पूर्व सरकारों द्वारा प्रतिपादित "लुक ईस्ट पालिसी" के स्थान पर "एक्ट ईस्ट पालिसी" द्वारा इस क्षेत्र के देशों के साथ चीन के समानांतर रिश्ते बनाने शुरू कर दिये है। चाहे दक्षिणी चीन–सागर में ताईवान के साथ तेल की खोज हो या वियतनाम को मध्यम दूरी की 'आकाश' मिसाईलों का निर्यात। हाल ही में 17 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की है तथा बंगलादेश के साथ 41 सालों से चला आ रहा भूमि–विवाद सुलझाया है। चीन के कान हाल ही में हिन्द महासागर में आयोजित भारत, अमरीका और जापान द्वारा नौसैनिक युद्वभ्यास "मालाबार–2017" से भी खड़े हो गये हैं। जिससे हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर एक सांकेतिक दबाव पड़ेगा। इसके साथ–साथ भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने अपने परमाणु सिद्वांत के "पहले प्रयोग नही" के सिद्वांत में भी परिवर्तन का मन बना लिया है।

चीन की आर्थिक विकास दर लगातार कम हो रही है तथा ऋण बढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहे चीन को ओबोर परियोजना आशा की आखिरी किरण नज़र आ रही है।

चीनी माल की उल्टी गिनती शुरू

देश का हर नागरिक चीन के प्रति सचेत होता जा रहा है। पिछली दीपावली पर जिस प्रकार से चीनी सामान के बहिष्कार की एक मुहिम स्वेच्छा से देश भर मे चली थी उसका व्यापक असर देखा गया। स्वदेशी जागरण मंच भी "राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान" के माध्यम से देशभर में चीन विरोध का जनजागरण अभियान चला रहा है। डोकलाम के मुद्दे ने आग में घी का काम किया है। आज देश का हर नागरिक विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा चीन के विरोध में खड़ा है लेकिन इस बीच नागपुर मैट्रो के लिए एक चीनी कंपनी को ठेका दिया जाना जनभावनाओं के खिलाफ है अगर चीन के मोर्च पर सरकार और आमजन के स्वर में एकता होगी तो चीन की हार निश्चित है। क्योंकि आज के आर्थिक युग में सैन्य हथियारों से ज्यादा गूंज आर्थिक हथियारों की होती है। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली प्रदर्शन रैली चीन के भारतीय बाज़ार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जिसकी गूँज विश्वभर में सुनाई देगी। डोकलाम चीन के लिए सचमुच बहुत मंहगा पड़ने वाला है। ❑❑

गंभीर संकट में चीन
ऐसे में भारत क्यों बने तारनहार?

(गतांक से आगे...)

अगला वैश्विक वित्तीय संकट चीन के कारण हो सकता है

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष सहित, विश्व की सभी प्रमुख वित्तीय अभिकृतियों (Financial Agencies) का मानना है कि चीन के कर्ज की समस्या को देखते हुए भविष्य में कोई बड़ा वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न होने की भी पर्याप्त संभावनाएं है। चीन की जो ब्रॉड मनी सप्लाई अर्थात् एम–2 (M2) जिसमें देश की रोकड़ मुद्रा व बैकों की जमाओं को जोड़ा जाता है, वह उसके सकल घरेलू उत्पाद की 208 प्रतिशत है। वर्ष 2016 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुद्रा आपूर्ति विश्व में सर्वोच्च है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह M2 मुद्रा आपूर्त्ति 170 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। अमरीका में यह अनुपात 80 प्रतिशत का ही है। जापान में यह अनुपात चाहे 240 प्रतिशत है, लेकिन जापान का वित्तीय तंत्र बैंक आधारित होने से यह उच्चानुपात चीन के जितना समस्याजनक नहीं है।

चीन का आर्थिक सशक्तिकरण अनुचित

चीनी वस्तुओं की खरीद से चीन का आर्थिक व सामरिक सशक्तिकरण भारत के लिये सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण होगा और हमें अपने संसाधन विकास के स्थान पर चीन–पाक से सुरक्षा में लगाने होंगे। इसके लिये भारत को अपने अबाध विकास के लिये चीन पर आर्थिक अंकुश लगाना सर्वाधिक आवश्यक है। चीन द्वारा की जा रही अनवरत शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के उपरांत भी, भारत द्वारा चीन को सर्वाधिक व्यापार सुविधाएँ देना और भी आत्मघाती कदम है। देश का सर्वाधिक 52 अरब डालर (3.5 लाख करोड़ रूपयों) का व्यापार घाटा, आज केवल चीन के साथ ही है। चीन से घोषित रूप में 4.25 लाख करोड़ रूपये व बड़ी मात्रा में अघोषित व कम बिल का माल भी देश में आ रहा है। आज देश में 5–6 लाख करोड़ रूपये का माल देश में आ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि चीन का जो आज देश में हम

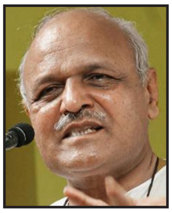

चीन, जो विगत 65 वर्षो से सर्वाधिक भारत विरोधी व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त है। ऐसे समय में जब हम संकट में फंसी चीन की अर्थव्यवस्था को उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करके चौपट कर सकते हैं, तब हम उसी की वस्तुयें खरीदकर उसे आर्थिक जीवनदान क्यों दे रहे हैं?

–प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

5–6 लाख करोड़ रूपये का माल आयात करते हैं, उसे हमें तत्काल बंद करना चाहिये। देश की जनता आज चीनी माल खरीदना बंद कर दे, तो यह चीन के प्रति हमारा सर्वोत्तम कदम सिद्ध होगा। अतएवं आज जब चीन एक आर्थिक, वित्तीय, बैंकिंग व कार्पोरेट संकट के ज्वालामुखी पर बैठा है, चीनी वस्तुओं का परित्याग ही इस संकट में विस्फोट की संभावना निश्चित करेगा। इससे चीन की संपूर्ण विश्व के लिए संकट उपजाने वाली गतिविधियों पर भी अंकुश लग सकेगा एवं विश्वभर में फैलते पर्यावरण संकट, विश्व के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद पर नियंत्रण संभव होने से संपूर्ण विश्व की मानवता राहत की सांस लेगी।

चीन की आर्थिक व सामरिक बढ़त में आज एक बड़ा योगदान भारत सरकार व हम भारतीयों का है। हम भारत में चीनी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उपयोग जो करते हैं। आज चीन और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 70 अरब डालर वार्षिक से अधिक है। इसमें 62 अरब डालर से अधिक के हमारे आयात हैं। यह 62 अरब डालर का माल लगभग चार लाख करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त चीन के उत्पाद बड़ी मात्रा में देश में बिना बिल के भी मिलते हैं या फिर कम बिल के भी मिलते हैं। बिना बिल का जो माल अपने देश में आ रहा है उसे जोड़ लें तो चीन से कुल आयात पांच से साढ़े पांच लाख करोड़ के हों तो कोई आश्चर्य नहीं है अगर 5.5–6.0 लाख करोड़ रूपयों का चीनी माल अपने देश में बिक रहा है, तो इसका कम से कम 10–12 प्रतिशत टैक्स तो चीन की सरकार को मिल रहा होगा। यदि हम 12 प्रतिशत टैक्स जीडीपी का अनुपात मानें तब, 60–70 हजार करोड़ रूपये के बराबर चीन की सरकार को राजस्व (Tax Revenue) की आय, हम भारतीय लोग, देश में चीनी माल खरीद कर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो देश हमारे लिए रक्षा संकट है, हम उस देश की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ रूपये का माल खरीद कर और सशक्त बना रहे हैं और उस देश की सरकार को 60–70 हजार करोड़ रूपये का कर राजस्व, उसका माल खरीदकर आप और हम दे रहे हैं। चीन इस 60–70 हजार करोड़ रूपये का राजस्व, जो उसे हम प्रदान कर रहे हैं, उसका एक भाग ही हमारे ऊपर सामरिक दबाव बनाने के लिए पर्याप्त है, एवं उससे ही वह पर्याप्त सामरिक दबाव बना लेता है। इस प्रकार आज हम ही यह सुरक्षा संकट अपने लिये खड़ा कर रहे हैं। चीन का माल पूरे देश में कौने–कौने में छा रहा है, चाहे 'टैक्सन' का केलकुलेटर हो या टी.सी.एल का टी.वी. हो, 'लिनोवा' का कम्प्यूटर हो, या अन्य ब्राण्डों के पेन व बच्चों के खिलौने हों, छोटे बल्ब हों, या बड़े विद्युत जनन संयंत्र (जेनरेटर) अथवा टेलीफोन एक्सचेंज, ये सब बड़ी मात्रा में अपने यहां चीन से आ रहे हैं। इसलिए, आज आवश्यकता इस बात की है कि, हम चीन से आने वाले सभी उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार करें। चीन के उत्पादों को चिन्हित करने में भी कठिनाई नहीं है क्योंकि उस पर ''मेड इन चाईना'' लिखा हुआ है। आज देश में सर्वाधिक कम्प्यूटर (PC) चीनी लीनोवो ही बिक रहे हैं। विदेश व्यापार में सर्वाधिक 52

वर्ष 2011–12 में देश का कुल 184 अरब डालर का विदेश व्यापार घाटा था। जबकि भारत-चीन व्यापार 2015–16 में 52 अरब डालर था।

अरब डालर का घाटा चीन के साथ ही है। वर्ष 2011–12 में देश का कुल 184 अरब डालर का विदेश व्यापार घाटा था, उसमें चीन के साथ ही इतना 41 अरब डालर का घाटा रहा है। भारत–चीन व्यापार 2015–16 में 52 अरब डालर था। इसमें चीन हमारे यहां 62 अरब डालर का माल निर्यात करता है, पर हम चीन को 9.0 अरब डालर का माल ही निर्यात कर पाये थे। वर्ष 2012–13 में भारत–चीन व्यापार 68 अरब डालर का था, उसमें हमारे निर्यात घटकर 13.5 अरब डालर के ही रह गये, जबकि चीन के निर्यात 54.5 अरब डालर थे। 2015–16 में हमारे निर्यात घटकर 9 अरब डालर रह गये, जो वर्ष 2012 में 17.03 अरब डालर के थे।

चीन का जिस प्रकार से आज हम पर सामरिक दबाव है, उसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी, दो प्रकार का दबाव बन रहा है। एक तो बड़ी संख्या में देश में कारखाने बंद हो रहे हैं। छोटे–छोटे

घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर रसायन व इंजिनियरिंग के क्षेत्र पर्यंत उद्योग एक के बाद एक चौपट हो रहे हैं। दूसरी और चीन ने अपना आर्थिक आधार इतना बढ़ा लिया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही चीन दुनिया की क्रमांक एक की अर्थव्यवस्था बन जायेगा। किसी जमाने में चीन दुनिया की सातवें क्रमांक की अर्थव्यवस्था था। वह बढ़ते–बढ़ते आज दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया है। जापान, जो दूसरे क्रमांक पर था, उसको पीछे छोड़कर चीन दूसरे क्रमांक पर आ गया है। चीन के कुल निर्यात आज अमरीका से भी अधिक हैं और अब चीन **विश्व का क्रमांक एक का निर्यातकर्त्ता देश बन गया है।** वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में भी चीन सर्वोच्च 22 प्रतिशत अंश है। हमारा अंश मात्र 2.1 प्रतिशत ही है। अमरीका भी आज 17.6 प्रतिशत के साथ क्रमांक दो पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अमरीका से अधिक निर्यात व्यापार आज चीन का है। ऐसे भी अनुमान हैं कि 2027 से 35 के बीच अमरीका, जो आज आर्थिक दृष्टि से क्रमांक एक की अर्थव्यवस्था है, उसे पीछे छोड़कर क्रय सामर्थ्य साम्य (परचेजिंग पॉवर पेरिटी) के आधार पर चीन विश्व की क्रमांक एक की अर्थव्यवस्था बन जायेगा। यदि ऐसा होता है तो अमरीका तो चीन से बहुत दूर है उसके लिए सीमा पर कोई तनाव की बात नहीं है। जबकि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, सीमा पर तनाव है और ऐसे में अगर चीन विश्व की क्रमांक एक की अर्थव्यवस्था बनकर उभरता है तब हम पर सैन्य दबाव भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। इसलिये देशवासियों को चीनी वस्तुओं की खरीद अविलम्ब बंद करनी चाहिये। सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिये कि, चीन को दी जा रही व्यापारिक सुविधाएं व परियोजनाओं के ठेके बंद करें। हाल ही में पिछले वर्ष भारतीय कंपनियों को चीनी मुद्रा 'युआन' में बाण्ड जारी कर ऋण जुटाने की जो छूट दी गयी है। उससे भी देश में चीनी पूंजीगत वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है।

चीन को आगे बढ़ाने के स्थान पर हमें आगे बढ़ना होगा

आज चीन, वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन (वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग व वैश्विक निर्यातों) में क्रमांक एक की शक्ति बनकर आर्थिक सुपर पावर बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सामरिक व रक्षा तैयारी में भी वह तेजी से आगे बढ़ एक वैश्विक शक्ति का स्तर पाने का प्रयास कर रहा है। हम चीनी वस्तुयें खरीदकर स्वयं का आर्थिक नुकसान कर चीन को सुपर पॉवर बनाने में सहायता कर अपने लिये संकट बढ़ाने का ही काम करेंगे। चीन को आगे बढ़ाने का काम करने के स्थान पर हमें स्वदेशी अर्थात 'मेड बाई भारत'

तालिका 1 : **भारत व चीन के आर्थिक सूचकों की तुलना**

Head	China		India	
GDP	2016	**$11.2 Trillion**	**$2.2 Trillion**	2016
GDP per capita	2016	**$8,113**	**$1,701**	2016
Expenditure	2015	**$3,515 billion**	**$629 billion**	2016
Expenditure (%GDP)	2015	**31.32%**	**27.90%**	2016
Expenditure Per Capita	2015	**$2,558**	**$475**	2016
Defence Expenditure (B.$)	2015	**$217.8 billion**	**$50.1 billion**	2015
Defence Expenditure P.C.	2015	**$159**	**$38**	2015
Moody's Rating [+]	5/24/2017	**A1**	**Baa3**	11/16/2016
S&P Rating [+]	12/16/2010	**AA-**	**BBB-**	1/30/2007
Fitch Rating [+]	11/21/2016	**A+**	**BBB-**	5/2/2017
Exchange Rate Euro / Chinese yuan	7/6/2017	**7.7443**	**73.7325**	7/6/2017
Inflation: CPI (overall index)	May-17	**1.50%**	**3.60%**	Nov-16
Motor vehicle production	2016	**2.8 crore**	**44.8 lac**	2016
Vehicles / 1,000 people	2014	**104.13**	**21.62**	2014
Exports [+]	2016	**$2098 billion**	**$264.0 billion**	2016
Exports as % GDP	2016	**18.70%**	**11.70%**	2016
Imports	2016	**$1587 billion**	**$359 billion**	2016
Imports as % GDP	2016	**14.15%**	**15.91%**	2016
Trade balance	2016	**Surplus of $510.7 bn**	**Deficit of $106 bn**	2016
Trade balance as % GDP	2016	**(+) 4.55%**	**(-) 4.21%**	2016
Population	2016	**1,382,710,000**	**1,326,802,000**	2016
Life expectancy	2015	**75.99**	**68.35**	2015
Number of homicides (Murder) [+]	2012	**11,286**	**41,623**	2014
Rate Homicides per 100.000 [+]	2012	**0.8**	**3.2**	2014
CO_2 Emission: Tons per capita [+]	2015	**7.73**	**1.87**	2015

Source: http://countryeconomy.com/countries/compare/china/india

तालिका 2 : **भारत व चीन के सामरिक सूचकों में अन्तर**

Title	India	China
1. Active Duty Military Personnel	Regular 1.3 Million	Regular 2.3 Million (World's Largest)
	Reserve 1.1 Million	Reserve 2.3 Million
2. Armoured Strength:		
a. Main Battle Tanks	1500	7950
b. Other Tanks	2400	1200
c. Armoured Fighting Vehicles	6500+	4600+
3. Projectiles:		
a. Self Propelled Guns	290	1710
b. Towed Guns	7500+	6246+
c. Multiple Rocket Launchers	300+	1770
4. Air Force (Fixed Wing Aircraft):		
a. Air Superiority Fighters	370+	662
b. Other/Ground Attack Fighters	258	1115
c. Transport Aircrafts	240+	782+
5. Air Force (Rotary Wing Aircraft):		
a. Helicopters (Including Army)	600+	832+
b. Attack Helicopters (Including Army)	Around 30	240+
6. Naval Prowess:		
a. Aircraft Carries	1 (With 4th Gen Aircraft)	1 (with 5th Gen stealth Aircraft)
	1 Under construction	6 More to be added
b. Destroyers	10	26
c. Frigates	14	47
d. Corvettes	26	25
e. Submarines	15	68
f. Other Vessels	Around 87	Around 450
g. Air Arm	Fighters 39 All Others 91 Helicopters 232	Fighters 324 All Others 245 Helicopters 114
7. Strategic Missiles	54	In Hundreds
8. Nuclear Missiles	90-100	260+

Source : http://topyaps.com/india-vs-china-military-strength

या 'मेड बाई इण्डिया' वस्तुएं व सेवाएँ खरीदकर स्वयं की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिये। चीन व हमारे बीच आर्थिक व सामरिक अंतर पर दृष्टि डालें तो हम सभी एकमत से सहमत होंगे कि हमें एक रूपये का भी कोई चीनी उत्पाद नहीं खरीदना चाहिये। नीचे तालिका क्रमांक 1 में भारत व चीन के बीच आर्थिक अंतर व तालिका 2 में सामरिक अंतर के कुछ बिन्दु दिये जा रहे हैं।

इन तालिकाओं से हमें स्पष्ट हो जायेगा कि भारत के प्रति सब प्रकार से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे चीन का एक रूपये से भी हमें आर्थिक सशक्तिकरण नहीं करना चाहिये। आर्थिक व रक्षा शब्दावली के अंग्रेजी शब्द यथा GDP या Ballistic Missile आदि ही अधिक चलन में होने से इन तालिकाओं में अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग किया है।

चीन–दक्षिण कोरिया विवाद से भी सीख लेने की आवश्यकता

चीन द्वारा भारत के विरोध व शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के क्रम में चीन अब तक केवल मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर ही 6 बार वीटो कर चुका है। ताज होटल के हमलावर लखवी की जमानत के बारे में भी चीन भारत के विरूद्ध वीटो कर चुका है। भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी कहने का भी चीन ने कड़ा विरोध किया है। जैश–ए–मोहम्मद के अगुवा संगठन अल–अख्तर–ट्रस्ट के मामले में भी भारत के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में विरोध कर चुका है। जमात उद्दावा के मामले में भी तीन बार वीटो करने के बाद चौथी बार ही वह वीटो का उपयोग करने से दूर रहा। लश्कर के आतंकी अब्दुर रहमान मक्की व आजम चीमा के मामले में भी चीन ने 2010 में वीटो उपयोग किया था। हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को भी वीटो किया था। चीन भारत की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर चुका है। बार–बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करता है और भारतीय सीमा के अंदर निर्माण कार्यों को भी वर्ष में कई बार बाधित करता है।

भारत के, 48 देशों के आणविक आपूर्ति समूह (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) में प्रवेश का भी केवल चीन ने ही विरोध किया है। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश का विरोध भी चीन ही कर रहा है। इन सब के उपरांत भी आज भारत चीन को आगे बढ़कर व्यापारिक सुविधाएं दे रहा है, चीन के पूंजी निवेश का स्वागत कर रहा है और भारत में चीन द्वारा 5 औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा व सहयोग दे रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत द्वारा पाकिस्तान में जा रहे सिंधु नदी के भारत के हिस्से के जल को रोकने की बात करने मात्र पर और पाकिस्तान के सर्जिकल कार्यवाही के विरूद्ध उसने जेग्बो नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का भारत का पानी ही अवरूद्ध कर दिया था। हमारा 38,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल का अक्सई चीन क्षेत्र तो आज भी चीन के नियंत्रण में है। जब चाहे हमारी सीमा में घुस आना सेना के बंकर तोड़ देना, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को आतंकित करना आदि आम बात हैं।

दूसरी ओर इसी 2017 के मार्च महीने के प्रारंभ में दक्षिण कोरिया द्वारा

उत्तर कोरिया से सुरक्षा के लिए जो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूट एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम (थाड मिसाइल तंत्र) तैनात किया गया है, इतनी सी बात पर एक सप्ताह भर में ही **चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित संचार माध्यमों ने कोरिया के आर्थिक बहिष्कार का व्यापक आह्वान कर दिया है** और दक्षिण कोरिया के विरूद्ध एक प्रकार के अघोषित प्रतिबंध की सी स्थिति उत्पन्न कर दी है। दक्षिण कोरियाई कंपनी लोट्टे, जिसके चीन में 99 स्टोर हैं और जो चीन में 260 करोड़ डालर की लागत में थीम पार्क का निर्माण कर रही थी, उसको काम बंद करने का आदेश दे दिया और उसके 79 स्टोर्स भी सस्पेंड कर दिये हैं। चीनी नागरिकों द्वारा पर्यटन हेतु दक्षिण कोरिया में जाना भी बाधित कर दिया है। चीनी ट्रेवल एजेंसियों पर यह दबाव भी बनाया है कि वे कोरिया भ्रमण के लिये समूह भ्रमण के पैकेज बेचना भी बंद कर दें। जबकि हम भारतीय आज बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष चीन भ्रमण पर जाते हैं। बड़ी मात्रा में चीनी वस्तुओं को क्रय समर्थन देते हैं। इस दृष्टि से हमें चीन द्वारा दक्षिण कोरिया के विरूद्ध दिखलायी चीनी राष्ट्रनिष्ठा व उनकी त्वरित प्रतिबद्धता पर गौर करना चाहिए कि मिसाइल स्थापना के 10 दिन में ही चीनी सरकार, सरकारी मीडिया, स्वैच्छिक संगठनों व जनता ने कोरिया का बड़े पैमाने पर आर्थिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया हैं। भारत के लिये भी आज, चीन के उत्पादों व निवेश के विरूद्ध आज अधिक तत्परतापूर्वक कार्यवाही का समय आ गया है।

यह अत्यंत आश्चर्यजनक ही है कि भारत के विरूद्ध 60 के दशक से जारी चीन की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के बाद भी आज हम साधारण उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों तक भारत के बाजारों पर चीन का नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया से सुरक्षार्थ तैनात की गई मिसाइलों की प्रतिक्रिया में ही चीन के सरकारी मीडिया, सरकार व आम उपभोक्ताओं ने दक्षिण कोरिया के विरूद्ध लगभग एक अघोषित आर्थिक प्रतिबंध के से हालात उत्पन्न कर दिए हैं जबकि, दक्षिण कोरिया ने ये मिसाइलें चीन को लक्ष्य करके नहीं, उत्तर कोरिया से प्रतिरक्षा के लिये तैनात की है। बस कोरिया ने यह टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (ठाड) मिसाइल तंत्र अमरीका से लिया है, इतनी सी बात पर चीन ने इतनी कड़ी कार्यवाही कर ली है। इसके विपरीत भारत द्वारा अपने आर्थिक व सामरिक हितों की सर्वथा अनदेखी कर हर प्रकार से चीन का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। **ऐसे में दक्षिण कोरिया द्वारा तैनात मिसाइलें चीन के विरूद्ध न होकर उत्तर कोरिया से रक्षार्थ तैनात करने पर भी चीन ने दक्षिण कोरिया के विरुद्ध एक अघोषित व्यापार व वाणिज्यिक युद्ध ही घोषित कर दिया है।** यह भारत के लिये एक उत्तम अनुकरणीय उदाहरण है। यदि चीनी अर्थव्यवस्था हमारे द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे बाजार के कारण वर्तमान संकट से उबर गयी, तो उसके लिये 'वन बैल्ट वन रोड़' परियोजना को पूरा करना सहज हो जायेगा। तब चीन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। इसलिये हमें चीनी वस्तुओं का परित्याग करना ही होगा। इस 'वन बेल्ट वन रोड़' परियोजना का संक्षिप्त विवेचन आगे किया जा रहा है।

भारत द्वारा अपने आर्थिक व सामरिक हितों की सर्वथा अनदेखी कर हर प्रकार से चीन का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है।

यदि आज भारत अपने चीन के साथ व्यापार घाटे को शून्य कर लेता है, जो 52 अरब डालर है, साथ ही यदि, जैसा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे है कि वे चीन के साथ जो अमरीका का 345 अरब डालर का व्यापार घाटा है, उसे शून्य कर लेंगे। ऐसा होने पर चीन का वह सारा व्यापार अतिरेक (ट्रेड सरप्लस) ही समाप्त हो जायेगा, जिसका उपयोगकर वह आज अफ्रीका–एशिया आदि में उसकी नव उपनिवेशकारी गतिविधियों में कर रहा है। उस सरप्लस के कारण ही चीन 'वन बेल्ट वन रोड' का निर्माण कर रहा है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्ला देश, केन्या, जांबिया सहित एशियाई व अफ्रीकी देशों में उपनिवेशकारी निर्माण व अन्य आर्थिक सहायता के कार्यक्रम चला पा रहा है। दूसरा, यदि हम आज चीनी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, तो आज की मंदी के दौर में कई चीनी कंपनियाँ आज निर्यात आधारित हैं। ऐसे में यदि हम चीनी माल का बहिष्कार कर देते है एवं विश्व में अन्यत्र भी सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करते हैं। ऐसा होने पर चीन में व्यापक उद्यमबंदी, बेरोजगारी व बैंकों के दिवालिया होने की शुरूआत हो सकती है। अब अगले अध्याय में 'वन बैल्ट वन रोड' परियोजना व भारत पर उसके प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। ❑❑

विदेशी प्रभाव से मुक्त हो नीति-निर्माण

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार में नीतिगत मोर्चे पर एक अहम बदलाव आकार ले रहा है और वह यह है कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय नीति–निर्माण प्रतिष्ठान पर विदेशी खासकर आंग्ल–अमेरिकन प्रभाव की जो रंगत चढ़ी थी, वह अब उतरती जा रही है। रघुराम राजन पहले ही विदा ले चुके हैं। अब अरविंद पानगड़िया भी समय से पहले अपना पद छोड़ने का एलान कर चुके हैं। वहीं लुटियन दिल्ली की अफवाहों की मानें तो आगे ऐसे और भी इस्तीफे हो सकते हैं। ऐसे में हमें शायद उनकी जगह पर ऐसे विशेषज्ञों की तैनाती देखने को मिल सकती है जो भारत की जमीनी हकीकत को कहीं बेहतर तरीके से समझते हों और जिनकी प्रतिबद्धता कार्यकाल पूरा होने तक टिककर काम करने की हो और जो बीच राह में जिम्मेदारियों को अधर में छोड़कर न चलते बनें। हालांकि 1991 के उदारीकरण के बाद देश में 'विदेशी' उत्पादों को लेकर भले ही रोमांच कुछ घटा हो, लेकिन मैकालेवादी मानसिकता से ग्रस्त नीति निर्माण प्रतिष्ठान को इस ग्रंथि से छुटकारा दिलाने में काफी लंबा वक्त लगा। इस बीच एक ऐसा शातिराना दुष्चक्र भरा दौर रहा है जिसमें घरेलू अकादमिक हलकों से निकले विशेषज्ञों को कमतर माना और उन्हें सरकार में उच्च पदों के योग्य नहीं समझा गया। इस दौरान 'आयातित विशेषज्ञों' की नियमित तौर पर आवक होती रही। इससे जुड़ी एक और समस्या अक्सर नजर आई कि देश में नीतियां बनाते हुए भी उन पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष यानी आइएमएफ और विश्व बैंक जैसे बहुस्तरीय संस्थानों या उन विश्वविद्यालयों का ही असर देखने को मिलता है जिनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा होती है। उनकी नीतिगत सलाह भी अमूमन सैद्धांतिक ज्यादा होती हैं जिनका भारत की धरातलीय वास्तविकता से दूर–दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वहीं भारतीय तंत्र के भीतर भी ऐसे नीतिगत सलाहकार लगातार उपेक्षित महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप वे समय से पहले ही पद छोड़ देते हैं। पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव भी खासा घातक रहा है।

देश को मार्क्सवादी विचारधारा की नकल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है जिसे

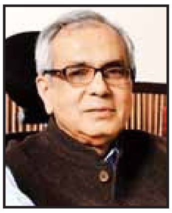

हालांकि 1991 के उदारीकरण के बाद देश में 'विदेशी' उत्पादों को लेकर भले ही रोमांच कुछ घटा हो, लेकिन मैकालेवादी मानसिकता से ग्रस्त नीति निर्माण प्रतिष्ठान को इस ग्रंथि से छुटकारा दिलाने में काफी लंबा वक्त लगा।

– राजीव कुमार

एमएन रॉय और बरास्ता ब्रिटेन उनके जैसे अन्य लोगों ने भारत पर थोपने का काम किया। इसकी वजह से दशकों तक हमारी नीतियां साम्यवादी कल्पनालोक के निरर्थक विचारों, समाजवादी लक्ष्यों, केंद्रीकृत नियोजन और निष्क्रिय नियमन की शिकार रहीं। एक सुसंस्कृत और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं वाले देश भारत में मार्क्सवादियों ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं पर प्रहार करने में भी कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। नतीजतन विकास रुक गया। निजी उद्यम पस्त पड़ते गए। साथ ही बेहद विस्तारित सरकारी ढांचे की छत्रछाया में ऐसा भ्रष्ट तंत्र विकसित हुआ जो गरीब हितों की बारी आने पर हद से हद जुबानी जमाखर्च में अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेता। इसके एकदम उलट हमारे नेता निःसंदेह ऐसे 'आयातित विशेषज्ञों' से प्रभावित होकर उन्हीं नीतियों के प्रति आसक्त रहे जो आमतौर पर ब्रेटनवुड्स की जुड़वा संतानों या अन्य विदेशी संस्थाओं और जानकारों की देन रहीं। विश्व बैंक और आइएमएफ को ही ब्रेटनवुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। वर्ष 1991 के बाद यह सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया, जब आइएमएफ ने मुद्रा अवमूल्यन, राजकोषीय किफायत और निजीकरण के लिए बाध्य कर दिया भले ही तब ये सभी पहलू व्यावहारिक न लग रहे हों। कुछ लोग जो शायद भूल जाते हों कि ब्रेटनवुड्स के अंधानुकरण के कितने घातक नतीजे हो सकते हैं, वे जरा नब्बे के दशक के अंत में एशियाई वित्तीय संकट को याद करें। उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया में जनकल्याण के मोर्चे पर हुए नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी सरकारों ने आइएमएफ के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और नीतियों के मोर्चे पर पूरी तरह मात खा गए। केवल मलेशिया ही कुछ हद तक प्रतिरोध कर पाया और अपनी स्थिर विनिमय दरों को बरकरार रखते हुए एशियाई संकट से उपजी वित्तीय सुनामी में किसी तरह खुद को कुछ महफूज रखने में सफल हो पाया।

चीन हमेशा ब्रेटनवुड्स संस्थानों के वैश्विक अनुभवों को बेहद गौर से सुनता है, लेकिन वह अपनी जमीनी हकीकत और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही सावधानीपूर्वक नीतियां बनाता है। हाल में पश्चिम–परस्त नीति विशेषज्ञों ने भारत में रीगन–थैचर शैली वाली 'न्यूनतम सरकार' की अवधारणा थोपने की कोशिशें की हैं। असल में यह निजीकरण का सैद्धांतिक नाम है जिसमें सरकार का अधिकांश काम निजी क्षेत्र द्वारा आउटसोर्स के जरिये होता है। वर्ष 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी इस सिद्धांत की नाकामी का जीता–जागता सुबूत है जिसने अमेरिका और बाद में यूरोप के वित्तीय तंत्र को तकरीबन लुंज–पुंज ही कर दिया। इस नाकामी के बाद भी शासन के इस सिद्धांत की हिमायत समझ से परे है। रीगन–थैचर सिद्धांत का मर्म यही है कि भारतीय राज्य यानी सरकार अपने नागरिकों को कानून–व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में भी अक्षम है। ऐसे में इन सभी सेवाओं का जिम्मा निजी क्षेत्र के सुपुर्द कर देना चाहिए।

यानी जो इनका खर्च उठाने में सक्षम हैं, वे इनका अपने स्तर पर बंदोबस्त करें। इस मॉडल में तमाम खामियां हैं। यह विषमता बढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे जरूरी सेवाओं के लिए गरीबों का वाजिब हक मारे जाने की आशंका काफी बलवती हो जाएगी। इससे भी बदतर बात है कि अभी भी यह बेलगाम आउटसोर्सिंग राज्य को ही 'शोषक संस्था' बनाने पर आमादा है जिसमें सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर 'लूटपाट' को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते का भी सवाल है। भारत अभी विकास के जिस पड़ाव पर है, उसके लिए रीगन–थैचर–आइएमएफ मॉडल उपयुक्त नहीं है। भारत को प्रभावी प्रदर्शन करने वाली 'विकासोन्मुखी सरकार' की दरकार है जो अपनी जनता के लिए प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही अपने उद्यमों के लिए कानून–व्यवस्था, बुनियादी ढांचा भी मुहैया कराए ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।

मौजूदा सरकार क्रमबद्ध रूप से विकासशील राज्य की छवि बनाने की अनथक कोशिशों में जुटी है। जब यह रणनीति कारगर होगी तो भारत की वृद्धि को ऐसी निर्णायक दिशा देगी जिसमें वह स्थाई रूप से ऊंची वृद्धि के चक्र में दाखिल हो जाएगा। 'द इकॉनमिस्ट' और 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' जैसे पश्चिमी पत्र–पत्रिकाएं मोदी सरकार द्वारा किए गए ढांचागत सुधारों से सुशासन की ओर बढ़ते कदमों की थाह लेने में नाकाम रहे हैं। यहां तक कि सब्सिडी के प्रत्यक्ष भुगतान जिसमें रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जा रही है, उसे भी दिखावटी सुधार बता रहे हैं। खास मंशा से की गई ऐसी आलोचना पर ध्यान दिए बिना सरकार को अपने लक्ष्य पर सफर जारी रखना चाहिए। इस लिहाज से रीगन–थैचर परंपरा वाले विदेशी विशेषज्ञों की अभी कोई जरूरत नहीं है। वैश्विक उत्पादन तंत्र, विश्व बाजार और वित्तीय एवं तकनीकी प्रवाह से अपनी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए विकासशील राज्य बनना भारत के लिए जरूरी शर्त होगी। यह एकीकरण हमें अपनी शर्तों और भारत की जटिल जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर करना होगा। ❑❑

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं पहले इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक और नीति आयोग के नामित उपाध्यक्ष हैं)।

कर्जमाफी से अलग भी सोचें

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बार–बार दोहराया है कि उनकी सरकार छोटे किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ कर देगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर करीब 9,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जबकि 10.25 लाख किसानों को लाभ होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके 34,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से 89 लाख छोटे किसानों को फायदा होगा। इसके बावजूद किसान आत्महत्याओं में तेजी आई है। पंजाब में पिछले बीस दिनों में 21 किसानों ने खुदकुशी की है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कर्जमाफी की घोषणा के बाद आत्महत्या की घटनाओं में तेजी क्यों आई है। महाराष्ट्र में पिछले दो हफ्तों में 42 किसानों ने खुदकुशी की। अकेले मराठवाड़ा क्षेत्र में 19 से 25 जून के बीच 19 किसानों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में पुलिस फायरिंग में पांच किसानों की मौत के बाद से 38 किसानों ने खुदकुशी की।

आदर्श रूप से कर्जमाफी की घोषणा के बाद किसान आत्महत्याओं में कमी आनी चाहिए थी। सभी किसानों को कर्जमाफी से लाभ भले न हो, पर छोटे और सीमांत किसानों के एक तबके को इससे फायदा होगा। इसलिए कर्जमाफी के बावजूद आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी होने से साफ है कि कृषि संकट हमारी समझ में ही कुछ बहुत ही गलत है। या तो कर्जमाफी मौजूदा कृषि संकट को हल करने का सही तरीका नहीं है या जिस तरह से कर्जमाफी की योजना तैयार और कार्यान्वित की जाती है, उससे छोटे किसानों को भी बहुत फायदा नहीं मिल रहा।

फसलों के लाभकारी मूल्य मिलने की उम्मीद के बिना किसानों की समस्या यह है

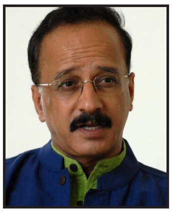

कर्जमाफी के बावजूद आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोत्तरी होने से साफ है कि कषि संकट हमारी समझ में ही कुछ बहुत ही गलत है। या तो कर्जमाफी मौजूदा कषि संकट को हल करने का सही तरीका नहीं है या जिस तरह से कर्जमाफी की योजना तैयार और कार्यान्वित की जाती है, उससे छोटे किसानों को भी बहुत फायदा नहीं मिल रहा।

– देविंदर शर्मा

कि अगली फसल के लिए वह जो ऋण लेने की योजना बना रहा है, उसे कैसे चुकाएगा। किसानों के बकाये कर्ज का एक हिस्सा भले माफ कर दिया गया हो, पर अगली फसल बोने के लिए उसे कर्ज लेना ही पड़ेगा। किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य से वर्षों से वंचित किया गया है, इसलिए कर्जमाफी को उनकी कृतज्ञता वापस पाने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। पर किसानों के संकट को कर्जमाफी से अलग करके भी देखा जाना चाहिए। अर्थशास्त्री और नीति–निर्माताओं को थोड़ा कल्पनाशील होकर सोचना चाहिए और ऐसे उपाय सुझाने चाहिए, जो दीर्घकालीन अर्थों में किसानों के हाथ में वास्तविक आय प्रदान कर सकें।

अन्न का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब का ही उदाहरण लीजिए। 98 फीसदी सिंचित कृषि भूमि और दुनिया में सबसे ज्यादा अन्न (गेहूं, धान और मक्का) उत्पादक होने के बावजूद पंजाब के प्रगतिशील किसानों की आत्महत्या का कोई कारण नजर नहीं आता। पर पंजाब किसान आत्महत्या का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि किसानों को उनकी उचित आय से वंचित किया गया है, जो अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य से मिलता है। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि पंजाब स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को उनकी उत्पादन लागत (सी–2 कॉस्ट) का पचास फीसदी मुनाफा क्यों नहीं दे सकता है, जहां एपीएमसी विनियमित मंडियों का व्यापक नेटवर्क है और जहां के गांव सड़कों से जुड़े हैं। यदि पंजाब यह घोषणा कर दे कि वह किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार मुनाफा देना चाहता है, तो उसे सालाना 8,237 करोड़ रुपये का खर्च वहन करना होगा। मेरी गणना के अनुसार गेहूं के

किसानों के बकाये कर्ज का एक हिस्सा भले माफ कर दिया गया हो, पर अगली फसल बोने के लिए उसे कर्ज लेना ही पड़ेगा।

मामले में प्रति क्विंटल उत्पादन लागत 1,203 रुपये आता है, अब इसमें 50 फीसदी मुनाफा जोड़ लीजिए, तो कुल मूल्य होता है 1,805 रुपये प्रति क्विंटल। चूंकि केंद्र द्वारा 1,625 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो राज्य सरकार को बाकी 180 रुपये प्रति क्विंटल देने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2016–17 के सीजन में 106.5 लाख टन गेहूं खरीदा गया, तो पंजाब सरकार पर कुल बोझ 1,917 करोड़ रुपये का पड़ेगा। अगर धान की फसल को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो दोनों को मिलाकर पंजाब सरकार पर 8,237 करोड़ रुपये का कुल वार्षिक बोझ पड़ेगा।

यदि आप समझते हैं कि 8,237 करोड़ रुपये एक बड़ी राशि है और पंजाब सरकार के दुर्लभ संसाधनों की बर्बादी होगी, तो एक बार फिर से विचार कीजिए, क्योंकि पंजाब के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य कभी नहीं दिया गया। पूर्ववर्ती बादल सरकार के समय गठित डॉ आरएस घुमन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, थोक मूल्य की तुलना में कम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने के कारण 1970 से 2007 के बीच पंजाब के किसानों को 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। किसानों को फसलों के उचित मूल्य से वंचित करने की प्रवृत्ति हरित क्रांति के दौर से जारी है। क्या यह किसानों की भरपाई का वक्त नहीं है? जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात होती है, तब कहा जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है, फसलों का मूल्य कम रखना चाहिए, नहीं तो खुदरा खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी। यानी उपभोक्ताओं को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसानों को गरीब रखा गया है।

पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या भी कृषि संकट से जुड़ी है। वर्षों से खेती अलाभप्रद बनती गई है और शहरों में रोजगार की संभावना भी क्षीण है, ऐसे में ग्रामीण युवक नशे के शिकार हो रहे हैं। नीति निर्माताओं के पास खेती को लाभप्रद बनाना आजीविका को बचाने का एकमात्र उपाय है। पंजाब में 18 लाख कृषक परिवार हैं और अगर ये परिवार खेती में आर्थिक देखेंगे, तो पंजाब फिर से कृषि क्षेत्र में गौरव हासिल कर सकता है।

पंजाब के लिए 'उड़ता पंजाब' की छवि को हासिल करने और अपनी गलतियों को सुधारने का यही वक्त है, जिससे वह देश के बाकी राज्यों के लिए फिर से आदर्श बन सकता है। पंजाब सरकार का काम सिर्फ अपने कर्मचारियों की सुध लेना और उनके लिए मासिक आय के साथ ज्यादा भत्ता सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि किसानों और कृषि मजदूरों का ख्याल रखना भी है। ❑❑

सरसों की जीएम फसल से जुड़े व्यापक सवाल

विश्व स्तर पर जीएम फसलों को लेकर जो तीखी बहस चल रही है वह इस समय भारत में जीएम सरसों पर तेज होते विवाद के रूप में सामने है। पक्ष–विपक्ष दोनों भली–भांति समझ रहे हैं कि यह मामला केवल किसी फसल की एक किस्म का नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। बड़ा सवाल यह है कि जीएम (जेनेटिकली मोडीफाईड या जेनेटिक रूप में संवंर्धित फसलों) को भारत में प्रवेश मिलेगा या नहीं।

इस समय तक भारत में केवल एक जीएम फसल की अनुमति मिली हुई है जो कपास की फसल बीटी कॉटन है, यानि जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन का हिस्सा नहीं है, यह फसल कई विवादों से घिरी रही। वर्ष 2009–10 में पहली खाद्य फसल के रूप में बीटी बैंगन को प्रवेश दिलाने का प्रयास कई शक्तिशाली तत्वों द्वारा हुआ। देशभर में अनेक किसान संगठनों, स्वास्थ्य व पर्यावरण अभियानों सहित अनेक वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। अनेक राज्य सरकारों ने भी अपना विरोध प्रकट किया। केंद्रीय सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने देश भर में इस विषय पर अनेक जन–सुनवाईयों का आयोजन करवा एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रतिष्ठित की जिसकी प्रशंसा दुनिया के अनेक देशों में हुई। अंत में उमड़ते विरोध के बीच बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई।

चंद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को जीएम फसलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयासों से सावधान रहें, क्योंकि इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि व खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है।

– **भारत डोगरा**

बीटी कॉटन व बीटी बैंगन विश्व की सबसे बड़ी बीज की बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसैंटो या उसकी उप कंपनियों की किस्में हैं। एक मुद्दा यह भी बना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय कृषि पर नियंत्रण की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अतः रणनीतिक तौर पर जीएम लॉबी ने यह निर्णय लिया कि अगली बार तैयारी ऐसी जीएम किस्म को स्वीकृति दिलवाने की, की जाएगी जो प्रत्यक्ष तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनी से न जुड़ी हो। इस संदर्भ में ही जीएम सरसों के बारे में बहुत प्रचार–प्रसार हुआ कि इससे उत्पादकता बढ़ सकती है। सरकार की ओर से भी इसके समर्थन में कई बयान आए।

दूसरी ओर न केवल विभिन्न संगठनों, अभियानों व वैज्ञानिकों का विरोध जारी रहा अपितु संघ परिवार के एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जीएम सरसों का कड़ा विरोध किया। इस पत्र में यहां तक कहा गया कि इससे पहले यूपीए सरकार के समय तो बीटी बैंगन के संदर्भ में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी, पर अब जीएम सरसों को बहुत अनुचित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

उधर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने लिखा कि मधुमक्खियों की परागीकरण (पॉलीनेशन) में प्रमुख भूमिका है, पर इसमें बहुत कमी आने का प्रमुख कारण जीएम फसलों से जुड़ी कीटनाशक दवाएं हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने स्वयं सरकार को कई बार इस संदर्भ में चेतावनी दी है पर

सरकार जीएम फसलों के मोह के कारण उनसे जुड़ी कीटनाशक दवाओं को भी छोड़ नहीं पा रही है। उन्होंने लिखा कि इन जीएम फसलों को कुछ कंपनियों ने हमारे देश पर इम्पोज कर दिया है।

इस तरह की आलोचना जब सरकारी पक्ष की ओर से भी आने लगी थी, उस समय 11 मई को देश में जीएम फसलों की नियमक एजेंसी जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसल समिति ने पर्यावरण मंत्रालय को जीएम सरसों की स्वीकृति संबंधी अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दी। अब आगे इस ओर ध्यान केंद्रित हो गया कि इस बारे में पर्यावरण मंत्रालय क्या निर्णय लेता है व सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या रुख रहता है। परंतु पक्ष–विपक्ष दोनों इस समय के निर्णयों के महत्त्व को समझ रहे हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कई जीएम खाद्य फसलों को विकसित किया है। एक बार इस खाद्य जीएम फसल को स्वीकृति मिल गई तो इससे उनकी अन्य जीएम फसलों की पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार हो जाएगी।

अतः इस समय यह जानना बहुत जरूरी है कि देश–दुनिया के स्तर पर जीएम फसलों व विशेषकर खाद्य फसलों के बारे में क्या तथ्यात्मक स्थिति सामने आ रही है।

अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस विषय पर तथ्य व विचार सामने रखे हैं। अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने एक इंडिपेंडेंट साईंस पैनल (स्वतंत्र विज्ञान मंच) का गठन किया। इस पैनल ने जीएम फसलों पर एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया है। इस दस्तावेज के निष्कर्ष में कहा गया है– "जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था, वे प्राप्त नहीं हुए हैं एवं यह फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रहीं हैं। अब इस बारे में व्यापक स्वीकृति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अतः जीएम फसलों व गैर जीएम फसलों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जीएम फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके है जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य व पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्त्ति नहीं हो सकती है, जिसे फिर ठीक नहीं किया जा सकता है। जीएम फसलों को अब दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए।"

जीएम फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है।

यूनियन आफ कन्सर्नड साईटिस्टस नामक वैज्ञानिकों के संगठन ने कुछ समय पहले अमेरिका में कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के उत्पादों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह असुरक्षित हैं।

जिस समय बीटी बैंगन की बहस जोर पकड़ रही थी, उस समय विश्व के 17 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएम प्रक्रिया से गुजरने वाले पौधे का जैव–रसायन बुरी तरह अस्त–व्यस्त हो जाता है जिससे उसमें नए विषैले या एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्त्वों का प्रवेश हो सकता है व उसके पोषण गुण कम हो सकते हैं या बदल सकते हैं। अब तक हुए अध्ययनों का निष्कर्ष यही है कि जीएम फसलों से उत्पादकता नहीं बढ़ी है। इन वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि विश्व में जीएम फसलों का प्रसार बहुत सीमित रहा है व पिछले दशक में इसकी नई फसलें बाजार में नहीं आ सकी हैं एवं किसान भी इन्हें स्वीकार करने से कतराते रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि जीएम तकनीक में ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके कारण कृषि में यह सफल नहीं है। जीएम फसलों में उत्पादन व उत्पादकता के मामले में स्थिरता कम है। इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के पत्र में यह भी कहा गया है कि जलवायु बदलाव के दौर में जीएम फसलों से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। जहां जीएम फसलों से उत्पादकता टिकाऊ तौर पर बढ़ने की संभावना नगण्य है, वहां इतना निश्चित है कि किसान चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बीज के लिए निर्भर हो जाएंगे व उनका खर्च काफी बढ़ जाएगा।

कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने जैव तकनीक के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रो. पुष्प भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसल कमेटी के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया। प्रो. पुष्प भार्गव सेंटर फार सेलयूलर एंड मालीक्यूलर बॉयलाजी हैदराबाद के पूर्व निदेशक रहे हैं व नैशनल नॉलेज आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं।

अपने एक चर्चित लेख में विश्व ख्याति प्राप्त इस वैज्ञानिक ने देश को चेतावनी दी है कि चंद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को जीएम फसलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयासों से सावधान रहें क्योंकि इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि व खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि इस कुप्रयास से जुड़ी एक मुख्य कंपनी का कानून तोड़ने व अनैतिक कार्यों का चार दशक का रिकार्ड है।

इन ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि जीएम सरसों की अनुमति का मुद्दा कितना महत्त्वपूर्ण है और इस संबंध में कितनी सावधानी जरूरी है। ❑❑

ग्रामीण विकास का दौर

भारत गांवों का देश है और इसमें से लगभग आधे से अधिक गांवों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन सुधारने के लिए अनेकों मोर्चों पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन शासन सत्ता की सर्वोपरि चिंता रही है। ग्रामीण विकास के कामों में मुख्य जोर रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क के साथ पढ़ाई और दवाई पर रहा है। नए शोध और अध्ययन से यह बात सामने आई है कि गत साढ़े तीन वर्षों में एनडीए सरकार की रफ्तार विकास के मोर्चे पर पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में तेज हुई है।

मालूम हो कि आजादी के बाद देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भयावह थी। यह वह दौर था जब भूख से मौतें होती थी। साल–दर–साल अकाल आता था और हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियों से गांव के गांव खत्म हो जाते थे। ऐसी ही अनेकों समस्याओं से देश को निजात दिलाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना, 1966 में अत्यधिक उपज प्रजाति योजना, 1985 में इंदिरा आवास योजना, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल योजना, 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की। इस क्रम में 1990 में जवाहर रोजगार योजना, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 2000 में अन्नपूर्णा योजना, 2001 में ग्रामोदय योजना प्रारंभ हुई। हालांकि इन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो सके, फिर भी देश में अपेक्षाकृत विकास हुआ। नई आर्थिक नीति और वैश्वीकरण के बाद ऐसे कार्यक्रमों की बाढ़ सी आई। 2005 में भारत निर्माण योजना, 2006 में ग्रामीण रोजगार योजना, 2006 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, 2007 में कृषि विकास योजना शुरू की गई। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार ने पूर्व की

आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं, इसलिए ग्रामीण विकास विकास की एकीकत अवधारणा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एकीकत विजन और मिशन के साथ आगे बढ़ रही है।

– अनिल तिवारी

योजनाओं का आकलन किया तथा इसे और अधिक गति देने के लिए एक चुस्त तंत्र विकास करने का ऐलान किया। वर्ष 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल भारत, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेवजयते योजना, स्वस्थ भारत मिशन तथा दीनदयान ग्राम ज्योति योजना का आगाज करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने का बीड़ा उठाया। अब अध्ययन से पता चलता है कि इस मोर्चे पर सरकार को आशातीत सफलता मिली है। विकास की तस्वीर सुहावनी दिख रही है।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी का ग्रामीण विकास का आह्वान आज भी प्रासंगिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में रह रहा है। प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए ग्रामीणों की कुल संख्या अब भी बहुत बड़ी है। पिछले तीन साल के दौरान ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है।

ग्रामीण विकास की चुनौतियां

बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, भूमि के साथ अन्य सभी संसाधनों का असामान्य बंटवारा, सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्या ग्रामीण भारत के विकास की बड़ी चुनौतियां हैं। साफ है कि ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसे ग्रामीण विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार के अब तक के प्रयासों से बुनियादी ढांचा खड़ा हो चुका है।

मूलभूत विकास की ओर बढ़ रहे कदम

भारत की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत लोग यानी लगभग 83.3 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। 16 करोड़ 78 लाख परिवारों के लिए पक्के मकान, पानी और शौचालय की सुविधाएं, सड़कें, बिजली, रोजगार, खेती के लिए खाद, बीज, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा देना किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं–

> **16 करोड़ 78 लाख परिवारों के लिए पक्के मकान, पानी और शौचालय की सुविधाएं, सड़कें, बिजली, रोजगार, खेती के लिए खाद, बीज, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा देना किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती है।**

- 2019 तक एक करोड़ पक्के मकान, सभी 5 लाख 93 हजार 731 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना।
- 2018 तक सभी गांवों में बिजली की व्यवस्था करना।
- 2022 तक सभी बेघरों को रहने के लिए आवास मुहैया करना।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सभी योजनाओं को इंटीग्रेटेड विजन और मिशन के साथ–साथ क्रियान्वित करता है।
- ग्रामीण विकास के लिए केंद्र की निम्न योजनाएं हैं– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएवाई), पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) व राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी)

पारदर्शिता और गुणवत्ता पर नजर

कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर निगरानी रखने के लिए जियो टैगिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, खातों से भुगतान, 5,000 से ऊपर के भुगतान नगद न करने जैसे नियमों से युक्त एक पुख्ता तंत्र महज दो सालों में ही खड़ा कर दिया है।

बजटीय आवंटन में बढ़ोत्तरी

ग्रामीण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट के आवंटन को लगातार बढ़ा रही है। 2016–17 में इन योजनाओं के लिए 95,000 करोड़ केन्द्र सरकार ने आवंटित किए थे। वहीं 2017–18 में इसे बढ़ाकर 105447.88 करोड़ खर्च करने की योजना है। अब केंद्र सरकार का लक्ष्य धन की उपलब्धता को बनाए रखने के साथ साथ काम की गति को तेज रखना है ताकि निर्धारित समय पर सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत गांवों के अकुशल वयस्कों रोजगार मुहैया कराता है। इस एक्ट के तहत एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के शारीरिक श्रम वाले रोजगार देने की गारंटी देता है।

2016–17 के बजट से इस योजना पर जहां केंद्र सरकार ने 38,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे, वहीं 2017–18 में 48,000 करोड़ रुपये धन का प्रावधान।

वर्तमान केंद्र सरकार ने ज्यादा दिए रोजगार

वर्ष में औसत रोजगार दिवस एक्ट में तो 100 दिनों के रोजगार की बात है, लेकिन अन्य सरकारों की तुलना में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में ग्रामीणों को साल भर में औसत रोजगार ज्यादा दिए गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान रोजगार लेने वालों की संख्या

और काम की उपलब्धता में कोई खास अंतर नहीं रहा है। जबकि इससे पहले की सरकारों में काम मांगने वाले ज्यादा होते थे और सरकार के पास काम कम।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2016 को पुरानी योजनाओं को समाहित करते हुए एक नयी महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी। इस योजना का लक्ष्य 2019 तक ग्रामीण भारत में एक करोड़ पक्के मकानों का निर्माण है।

2012–13 से 2015–16 के बीच प्रतिवर्ष 12 लाख ही मकान बन पाये थे। अब हर साल लगभग 33 लाख मकान का लक्ष्य। 2015–16 के लक्ष्य प्राप्ति में कमी को 2016–17 की योजना के तहत अक्टूबर तक 77 लाख मकान बनवाकर पूरा करना है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना

कौशल विकास और रोजगार निर्माण केंद्र सरकार के एजेंडा का मुख्य केंद्र बिंदु है। 25 सितंबर 2014 को शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी युवाओं को आजीविका के लिए स्वावलंबी और क्षमतावान बनाना है। डीएवाय के ग्रामीण घटक को 2014 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तीन साल (2014–2017) के भीतर भारत के गांवों के करीब 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्षमतावान बनाना है।

इस उद्देश्य के लिए युवा की परिभाषा में 15 वर्ष या उससे ज्यादा आयु वाले युवाओं को शामिल किया गया। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से शुरू किए गए विशेष केंद्रों पर आयोजित किए गए।

क्या है दीन दयाल अंत्योदय योजना?

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम नवबंर 2015 में दीन दयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इस योजना में गांवों के गरीब को आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना में विश्व बैंक का भी अंशदान है। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाना, उनको रोजगार व्यापार की ट्रेनिंग और धन मुहैया कराना है।

इस योजना के तहत कुल 642 सेंटर पर 329 प्रकार के कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है। कौशल विकास योजना में सीखे हुए युवकों को सरकार आवास योजना और अन्य योजनाओं में काम देती है। योजना के तहत 28 फरवरी, 2017 तक 1,48,227 लोगों को कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से 79,401 प्रशिक्षितों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है।

23 मार्च, 2017 तक 1,52,179 कार्यों के जरिये 4,99,1244 किमी सड़कें पूरी हो चुकी हैं। शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

ऐसा कम ही होता है कि कोई योजना के क्रियान्वयन की अवधि घटाई जाती हो। लेकिन केंद्र सरकार ने हर गांव को 2022 तक जोड़ने की योजनावधि की सीमा को घटाकर 2019 कर दिया है। आज हर रोज 30 किमी सड़कें बन रही हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों में अगले चार वर्षों में 5411 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों में 11,700 करोड़ की लागत से अगले चार वर्षों 26 पुलों का निर्माण का लक्ष्य।

फरवरी 2017 से सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत सांसदों द्वारा अंगीकृत गांवों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों से जोड़ा दिया गया।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क–संपर्क से वंचित गांवों को बारह मासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है ताकि 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाला गांव (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 व्यक्ति) सड़कों से जोड़ा जा सके।

23 मार्च, 2017 तक 1,52,179 कार्यों के जरिये 49,91,244 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं। शत–प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया था। लेकिन इसने वास्तविक गति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पकड़ी।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस समय इस कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलंगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्पूर्णा योजना शामिल है। इस सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीधा खाते में धन देने की सुविधा वर्तमान केंद्र सरकार ने शुरू की है और सभी खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया।

भारत के गांवों में रहने वाले लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं, इसलिए ग्रामीण विकास विकास की एकीकृत अवधारणा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एकीकृत विजन और मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। ❑❑

सुधार की राह देखती देश की शिक्षा व्यवस्था

हमारा देश विश्वगुरु बनने के सपने देखता है, लेकिन जिस देश के करोड़ों छात्र स्कूल ही नहीं जा रहे हों, वो विश्वगुरु कैसे बन सकता है? बच्चों को पढ़ाई से दूर करने वाली मजबूरियों को हमें खत्म करना होगा ताकि हमारा देश एक कमजोर राष्ट्र बनकर ना रह जाए।

– **आशीष रावत**

देश में शिक्षा के स्तर को लेकर एक गैर सरकारी संगठन 'प्रथम' ने ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर को दर्शाने वाली एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का एक अंक प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के 589 जिलों के ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया गया। इस सर्वे में 5,62,305 बच्चों के शिक्षा के स्तर को नापा गया। आपको जानकर दुःख होगा कि ग्रामीण भारत में बच्चों की पढ़ाई का स्तर या तो गिर रहा है या फिर इसमें मामूली सुधार दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 में ग्रामीण भारत में आठवीं कक्षा के करीब 53 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वर्ष 2016 आते–आते ये आंकड़ा 55 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया। अंग्रेजी ही नहीं ग्रामीण भारत में आठवीं कक्षा के छात्र गणित के सामान्य जोड़ने–घटाने के काम भी नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2016 में आठवीं कक्षा के 76.7 प्रतिशत छात्र दो संख्याओं को घटा नहीं पाए, जबकि 57 प्रतिशत छात्र भाग करना यानी डिवाइड करना नहीं जानते थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या 8,40,546 है। देश में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की संख्या 12 करोड़ 91 लाख है। इन प्राइमरी स्कूलों में 5,39,000 शिक्षकों की कमी है। शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में तीस बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत के प्राइमरी स्कूलों में 27 बच्चों पर एक अध्यापक है। ये सरकारी आंकड़े हैं और कई बार इन आंकड़ों को निजी तौर पर कराए गए सर्वे से चुनौती मिलती रहती है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है या सुधर रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश के आठ करोड़ चालीस लाख बच्चे विद्यालय ही नहीं जाते हैं। अब तक ये संख्या और बढ़ गई होगी। ये आंकड़ा बहुत गंभीर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आठ करोड़ चालीस लाख छात्रों की संख्या इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। यानी हमारे देश में स्कूल ना जाने वाले छात्रों की संख्या इन विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इसके अलावा हमारे देश के 78 लाख से अधिक बच्चे स्कूल जाने के साथ–साथ रोजी–रोटी कमाने के लिए काम भी करते हैं। विद्यालय के साथ–साथ काम करने वाले बच्चों में 57 प्रतिशत लड़के हैं, जबकि 43 प्रतिशत लड़कियां हैं। इन 78 लाख बच्चों में से 68 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो खेती–बाड़ी जैसे काम करते हैं। आपको बता दें कि जो आठ करोड़ चालीस लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो शिक्षा के अधिकार के दायरे में आने वाले कुल बच्चों के बीस प्रतिशत हैं। यानी इन बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन इसके बाद भी तमाम मजबूरियों की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्या आपको पता है कि भारत के करीब साढ़े आठ करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।

वर्ष 2015 की एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक देश में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 48 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं, जो सेकेंड क्लास की किताबें पढ़ पाते हैं, यानी पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बाकी 52 फीसदी छात्र, दूसरी कक्षा की किताबें भी नहीं पढ़

सकते। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले हर दो छात्रों में से एक छात्र तीसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाता। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले हर चार छात्रों में से एक छात्र दो अंकों को जोड़ और घटा नहीं पाता। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले हर चार छात्रों में से एक छात्र को गुणा और भाग करना नहीं आता है। ग्रामीण भारत में आठवीं कक्षा तक के 44 प्रतिशत से अधिक बच्चे गुणा और भाग नहीं कर पाते। जबकि पांचवी कक्षा के 75 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। ये आंकड़े हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का आईना हैं। जब हमारे देश के स्कूल बच्चों का ये हाल है तो बेहतर शिक्षा का पूर्ण स्वराज मिलना कितना मुश्किल होगा? जब भी स्कूल की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है। देश के 3680 सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ते हैं।

देश के बीस फीसदी शिक्षक अयोग्य यानी बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में 84 फीसदी शिक्षकों को आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार जैसी जरूरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। 42 फीसदी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इतना सब होने के बावजूद हमारा सिस्टम ये रट लगाए रहता है कि 'स्कूल चले हम' लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का इतना बुरा हाल है तो फिर बच्चे कैसे स्कूल जाएं और क्यों स्कूल जाएं? जिस देश में शिक्षा के हालात इतने खस्ताहाल हों, उस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अनपढ़ होने की बात जानकर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2014 के मुताबिक भारत में 28 करोड़ 70 लाख लोग पढ़–लिख नहीं सकते। ये संख्या फ्रांस की कुल जनसंख्या से चार गुना है।

एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा बच्चा बड़ा होकर बेरोजगार युवक बनता है और एक बेरोजगार युवक आगे चलकर देश पर बोझ बनता है और बेरोजगारी का ये बोझ बढ़ता ही जाता है।

यानी दुनिया की 37 फीसदी निरक्षर आबादी भारत में रहती है। इसकी वजह होती है स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों का ना होना और पढ़ाई के माहौल का अभाव, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो देश में शिक्षा के अच्छे दिन आ सकते हैं।

एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा बच्चा बड़ा होकर बेरोजगार युवक बनता है और एक बेरोजगार युवक आगे चलकर देश पर बोझ बनता है और बेरोजगारी का ये बोझ बढ़ता ही जाता है। हाल ही में जारी साल 2011 की जनगणना के आंकड़े शिक्षा के अधिकार की चिंताजनक स्थिति की तस्वीर सामने रखते हैं। इसके मुताबिक भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 78 लाख है जो स्कूल तो जाते हैं मगर उनको परिवार की तरफ से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि 8.4 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। हालांकि काम करने वाले बच्चों की संख्या स्कूल जाने वाले बच्चों की पूरी आबादी की तुलना में कम है, मगर यह संख्या काफी बड़ी है। जो यह दर्शाती है कि परिवार और बच्चों द्वारा शिक्षा को कितना कम महत्व दिया जा रहा है। एक स्कूली बच्चे ने कहा, "मेरे स्कूल में कम शिक्षक है। मैं तीन किमी. से पैदल स्कूल आता हूं। पूरा दिन खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ भैंस चराने के लिए चला जाऊं।" यह स्थिति बच्चे को स्कूल से विमुख करने वाली है, जिसका एक प्रमुख कारण स्कूल में शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में ऐसी स्थिति भी नजर आती है कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को हिन्दी की किताब पढ़ने में परेशानी हो रही है। काम व अन्य कारणों से स्कूल में अनियमित होने वाले बच्चे के सीखने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर शोध व जमीनी रिपोर्टों में बार–बार यह तथ्य सामने आता है। वहीं आदिवासी इलाकों में और गांवों में परिवार के लोगों को इस बात की फिक्र नहीं होती कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं। अगर बच्चे ने पहली–दूसरी कक्षा में पढ़ना सीख लिया तो ठीक है। पढ़ाई में कमजोर होने वाली स्थिति में स्कूल छूटने की आशंका और बढ़ जाती है। हमारे देश में 8.4 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। यह संख्या शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आने वाले कुल बच्चों की संख्या का बीस फीसदी है।

शिक्षा के अधिकार कानून तहत किसी बच्चे को फेल नहीं करने की नीति के कारण भी अभिभावक बच्चों को काम पर लगा देते हैं और स्कूल केवल परीक्षा वाले दिनों में भेजते हैं, इस वजह से भी काम करने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ी है। स्कूल के साथ–साथ काम पर जाने वाले बच्चों में 57 फीसदी लड़के हैं, जबकि 43 फीसदी लड़कियां हैं। काम करने वाले बच्चों में कुछ की उम्र मात्र छह साल है। हमारा देश विश्वगुरु बनने के सपने देखता है, लेकिन जिस देश के करोड़ों छात्र स्कूल ही नहीं जा रहे हों, वो विश्वगुरु कैसे बन सकता है? बच्चों की ये मजबूरियां ही देश की कमजोरियां हैं इसलिए बच्चों को पढ़ाई से दूर करने वाली इन मजबूरियों को हमें खत्म करना होगा ताकि हमारा देश एक कमजोर राष्ट्र बनकर ना रह जाए। ❑❑

वर्तमान शिक्षण में रचनात्मकता आवश्यक

शिक्षण एक रचनात्मक विद्या है। यह विद्यार्थियों की मौलिकता व सृजनशीलता को प्रकट करने के साथ उनमें सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता भी प्रदान करती है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच ज्ञान के प्रवाह को रचनात्मकता के माध्यम से ही स्वतः स्फूर्त बनाया जा सकता है तथा सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में परिपूर्णता आती हैं। विद्यार्थी में अपने अज्ञान को दूर करने व कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रहती है। शिक्षक ही विद्यार्थी में ज्ञान की रिक्तता को पूर्ण कर शिक्षार्थी के जीवन को संपूर्ण बना सकते है। क्रियात्मक एवं भावात्मक जुड़ाव द्वारा प्रदान किया गया शिक्षण विद्यार्थी को जीविका प्राप्त करने के अनेक विकल्पों के साथ वास्तविक ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान आधारित रचनात्मक शिक्षण ही विद्यार्थी को सुखी व समृद्ध जीवन की आधारशिला प्रदान करता है। उसको भविष्य में आने वाली कठिन समस्याओं का हल ढूँढने व संघर्ष करने का भी विवेक प्रदान करता है।

भारत में वैदिक काल से शिक्षण में रचनात्मक कार्यों द्वारा संपूर्ण जीवन को उत्कृष्ट बनाने का उद्देश्य निहित रहता था। अतः विद्यार्थी में शिक्षा के माध्यम से सृजनशीलता व कर्मठता के गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता था। जीविका प्राप्त करने संबंधी विधाओं के साथ, उसे कौशल प्रशिक्षण एवं वेदों, उपनिषदों का ज्ञान भी दिया जाता था। यह समग्र शिक्षण विद्यार्थी के उन्नत व्यक्तित्व का गठन करने में सहायक होता था। अपने आसपास की भौगोलिक व सामजिक परिस्थितियों को जानना व अन्वेषण करना भी व्यवहारिक ज्ञान के लिये आवश्यक होता था। प्रत्येक विद्यार्थी की समाज के लिये अपनी उपयोगिता सिद्ध करने पर ही उसके शिक्षण का वास्तविक मूल्यांकन होता था। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरू द्वारा शिक्षार्थी को सामाजिक जीवन में ज्ञान का रचनात्मक उपयोग करने का संदेश तैत्तरीय

प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति से प्रेरित रचनात्मक शिक्षण विद्यार्थी के अन्दर सुप्त मौलिकता व सजनशीलता को प्रकट करेगा। शिक्षण में रचनात्मकता के माध्यम से विद्यार्थी में बड़ा से बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता विकसित हो सकेगी तथा राष्ट्रीय विकास के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

— डॉ. रेखा भट्ट

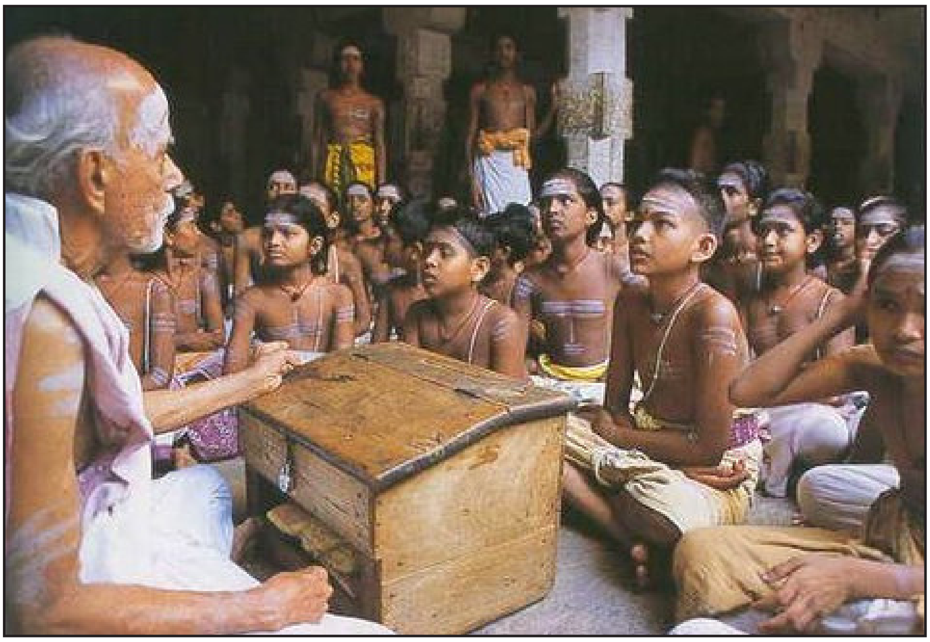

उपनिषद में प्रदान किया गया है–
"सत्यंवद धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमादः।"

अर्थात्–"सत्य बोलने धर्म का पालन करने व स्वाध्याय द्वारा निरंतर ज्ञान में वृद्धि करते हुए संपूर्ण मानवता की सेवा ही शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है।"

रामायण व महाभारत जैसे भारत के प्राचीन महाकाव्य सृजनधर्मिता की अनुपम देन है, जो आज भी जीवन संघर्ष में व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करते है। भारतीय विद्वान आर्यभट का खगोल शास्त्र व शून्य की खोज प्राचीन भारतीय शिक्षण में नवाचार के अनुपम उदाहरण है। विश्व में मानवता को भारत की महानतम देन है। कठिन गणितीय सूत्रों का सरल हल देने की दक्षता से हतप्रभ कर देने वाले रामानुजम के असीमित ज्ञान को विदेशी शिक्षण जगत ने पहचाना और आगे बढ़ाया। महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन ने न्यूनतम साधनों में विश्व को रमन सिद्धांत देकर भारत की अन्वेषण क्षमता का परिचय दिया। शिक्षा में रचनात्मकता के माध्यम से जीवन मूल्यों को समाहित करने वाले असंख्य उदाहरण आज भी भारत की अमूल्य धरोहर है।

मुगलकाल के दौरान भारतीय शिक्षा के वैज्ञानिक आधार में कमी आई तथा शिक्षण में धार्मिकता का प्रभाव बढ़ने के बाद भी जीवन मूल्यों में कमी नही आ सकी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मैकालयी शिक्षण पद्धति प्रचलित हुई तथा भारतीय गुरूकुल शिक्षा प्रणाली को षड़यंत्रपूर्वक भारत के कोने–कोने से मिटा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षण पद्धति में पुस्तकीय अवधारणाओं को ही अंतिम सत्य मान लिया गया तथा जीवन के सत्यों को जानने, समझने तथा जन–जन के लिये उजागर करने के प्रयास समाप्त कर दिये गये। विद्यार्थी के सोचने विचारने व अपनी कल्पनाओं को साकार करने के अवसर समाप्त होते गये। अपनी कलात्मकता को स्वाभाविक रूप से विकसित करने संबंधी गतिविधियां नहीं होने के, परिणामस्वरूप विद्यार्थी की रचनात्मकता पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों व परीक्षाओं के वार्षिक अनुक्रम में बंध कर रह गई।

आजादी के 70 वर्षों बाद भी हमारी शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षण पद्धति को ढ़ोते रहने के कारण एक औपचरिकता बन कर रह गई है। शिक्षा की अनिवार्यता जैसे नियमों ने इसे एक अपरिहार्य आवश्यकता बना दिया गया है। यह शिक्षा कुछ मात्रा में रोजगार तो प्रदान कर सकती है किंतु शिक्षण में नवाचार, वैज्ञानिकता व संवैधानिक मूल्यों का समावेश नही करती। अंग्रेजी व अंग्रेजियत के अनुकरण से शिक्षण में रचनात्मकता आधारित भारतीय शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है। आज स्वाध्याय तथा अन्य मूल्यों को जीवन के लिये अनावश्यक माना जाने लगा है। वर्षो पुरानी पुस्तकीय अवधारणाओं व जानकारियों को कण्ठस्थ कर अधिकतम अंक प्राप्त करना ही विद्यार्थी के जीवन की उपलब्धि बन गयी है। स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करना और इसका समाज के हित के लिये अनुप्रयोग संभव नहीं होता। अतः विद्यार्थी में नवीन सृजन करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न नहीं हो पाती। शिक्षण की वास्तविक जीवन से भिन्नता एवं अनुपयोगिता शिक्षार्थी को सामाजिक सारोकारों से दूर कर देती है।

अंग्रेजी व अंग्रेजियत के अनुकरण से शिक्षण में रचनात्मकता आधारित भारतीय शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है।

आधुनिक शिक्षण रोजगार प्राप्ति पर केंद्रित है, अतः इसे ही व्यवहारिक मान लिया गया है। एक ओर शिक्षक के लिये शिक्षा मात्र आजीविका प्राप्ति का साधन है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी के लिये कक्षा कक्षीय शिक्षण किसी प्रकार की रूचि पैदा करने में असमर्थ होने के कारण शिक्षा उसके लिये भारी बोझ बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ने लगते है।

आजादी के समय की तुलना में विद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या में अपार वृद्धि होते हुए भी विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जा रही हैं। वहीं जानकारी बढ़ाने के लिए ऑनलाईन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। आज अनेक क्षेत्रों में प्रवेश की आधुनिकतम तकनीकी व कार्य प्रणाली से विद्यार्थी अवगत नही होते है। अपने विषय में निष्णात होने के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भी रोजगार पाने की पात्रता नहीं रखते। 12–15 वर्ष के आधारभूत शिक्षण द्वारा कैरियर बनाने में विद्यार्थी अपनी समस्त ऊर्जा व्यय कर देते है। आधुनिक शिक्षण में वर्षों से चले आ रहे पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षक जानकारियों का दोहराव करते हैं तथा विद्यार्थी उन्हें स्मरण कर परीक्षा में सफल हो जाते है। रचनात्मकता के अभाव में विद्यार्थी को अपनी क्रियाशीलता तथा विचारों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अवसर नहीं मिलते। आज शिक्षित विद्यार्थी स्वयं की सोच विकसित करने व अपने दृष्टिकोण से विषय को समझने व विश्लेषण करने की सामर्थ्य ही रखते।

यदि प्राथमिक स्तर से ही रचनात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थी की विशिष्टताओं को पहचान कर सही दिशा दी जाए तो उच्च शिक्षा में किये जाने वाले शोध व अनुंसधान भी मौलिक व प्रासंगिक बन सकेंगे। डिग्रीधारी विद्यार्थी शिक्षित किन्तु अनुपयोगी

मानव संसाधन की भीड़ नहीं बनेंगे। आज रोजगारीय प्रतिस्पर्धा को ज्ञान, कौशल व मूल्यों पर आधारित रचनात्मक शिक्ष से पृथक करके देखना होगा। शिक्षक द्वारा कक्षा–कक्षीय शिक्षण को जीवंत बनाने के लिये विषय संबंधी नवीन प्रयोगों व तथ्यों को प्रस्तुत करने से तथा प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा विद्यार्थी में विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। यह जिज्ञासा ही विद्यार्थी को नया सोचने व खोज करने की प्रेरणा देती है।

रचनात्मक का गुणात्मक विश्लेषण संभव है, किन्तु वर्तमान में प्रचलित संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा विद्यार्थी की प्रतिभा का आकलन न्यायसंगत नहीं रहता। विद्यार्थी के आधे अधूरे ज्ञान का सामूहिक रूप से अंकों के स्कोर के रूप में किया गया मूल्यांकन उसे हतोत्सहित करता है। शिक्षण के साथ तात्कालिक परीक्षण एवं मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की कमियों का पता कर उनमें सुधार के प्रयास किये जा सकते हैं। उनकी योग्यता व प्रतिभा को पहचान कर उन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। विद्यार्थी अपनी संपूर्ण मानसिक शक्ति के साथ अपने अधिकतम प्रयासों को फलीभूत करेगा। इसके परिणामस्वरूप रचनात्मक उपलब्धियों को सराहने व पुरस्कृत करने से विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

आजकल ऑनलाईन शिक्षण के तेजी से बढ़ते हुए प्रभाव के बाद भी पुस्तकों और पुस्तकालयों का महत्व आज भी कम नही हो सका है। इनके माध्यम से शिक्षण पद्धति में आज पुनः स्वाध्याय को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मोबाइल के बढ़ते उपयोग से शिक्षण में लेखन व श्रवण की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है जो सृजनात्मकता के लिये आवश्यक है। सुनकर लिखने के अभ्यास से विद्यार्थी में सीखने व मनन की प्रक्रिया सहजरूप से विकसित होगी। शिक्षक द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिकता पर आधारित कार्ययोजनाएं विद्यार्थी की क्रियाशीलता व दक्षता को बढ़ाने में सहायक होगी।

विद्यार्थी की रचनात्मकता बढ़ाने के लिये आवश्यक सभी उद्देश्यों का शिक्षा नीति में स्पष्ट उल्लेख करके ही रचनात्मक शिक्षण को क्रियान्वित किया जा सकता है। शिक्षण में रचनात्मकता का समावेश होने पर विद्यार्थी के शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं रहेगा, वरन् वह स्वयं के उत्थान के साथ सामाजिक उन्नयन के लिये भी प्रयत्नशील रहेगा। प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति से प्रेरित रचनात्मक शिक्षण विद्यार्थी के अन्दर सुप्त मौलिकता व सृजनशीलता को प्रकट करेगा। शिक्षण में रचनात्मकता के माध्यम से विद्यार्थी में बड़े से बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता विकसित हो सकेगी। तथा राष्ट्रीय विकास के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

पथ्य पालन से ही रोग निवारण

वर्तमान समय में आयुर्वेद चिकित्सालय में ऐसे रूग्णों की संख्या बढ़ रही है, जो अपने दैनन्दिन आहार व विहार के माध्यम से स्वस्थता को बरकरार रखना चाहते है या रोग को त्वरित गति से ठीक करना चाहते है। जनसामान्य के सामने यह तथ्य आ रहा है कि एक जैसे ही आहार लेने के बावजुद परिवार के अन्य सदस्य को कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है?

आचार्य लोलिम्बराज ने कहा है कि–

'पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषध निषेवणैः।
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषध निषेवणैः।।'

अर्थात्–पथ्य पालन करने से रोग का अपने आप ही निवारण हो जाता है अर्थात् औषध की आवश्यकता नहीं है, और अगर रोगी पथ्य पालन नहीं करता है तो भी औषध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर रोगी लगातार पथ्य पालन नहीं करता है तो उसे रोग मुक्त करना आसान नहीं है। अगर औषध ग्रहण काल में थोडा बहुत रोग के विभिन्न लक्षणों में आराम लगता भी है तो वह सदा के लिये आराम तो नहीं आता है–अन्ततोगत्वा पथ्य पालन तो करना ही पडता है। हम समाज में ऐसे अनेक व्यक्तियों को यह कहते हुए सुनते है कि 6–8 महीने या सालभर दवाईयाँ लेने से थोडा बहुत आराम था, मगर दवाईयां बंद करते ही वैसा ही हो गया या स्थिति ज्यादा खराब है, फिर दूसरे चिकित्सक को ढूढने लगते है मगर पथ्य पालन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। महात्मा गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक 'आरोग्य की कुंजी' में लिखा है कि व्यक्ति के पेट में दर्द है तो किस चिकित्सक की सलाह ली जाए,

पथ्य पालन करने से रोग का अपने आप ही निवारण हो जाता है अर्थात् औषध की आवश्यकता नहीं है, और अगर रोगी पथ्य पालन नहीं करता है तो भी औषध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर रोगी लगातार पथ्य पालन नहीं करता है तो उसे रोग मुक्त करना आसान नहीं है।

– वैद्या हेतल दवे

उस पर विचार किया जाता है और तो और समाज में मिलने वाले अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी यह सलाह दी जाती है कि अमुक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, किन्तु कल ऐसा क्या खाया गया कि जिससे पेट में दर्द है उसका कोई भी विचार नहीं करता। अर्थात् पथ्यापथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। अस्तु।

इस का अर्थ यह है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है या रोग से सदा के लिये मुक्त होना चाहता है तो उसे अपनी प्रकृति के अनुसार पथ्य आहार का ग्रहण करना अतिआवश्यक है। आहार द्रव्य व पीने योग्य द्रव्य का गुण सहित वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, अगर उस विधि का पालन करते हुए उन द्रव्यों का ग्रहण किया जाए तो हमें इन गुणों की प्राप्ति हो सकती है। पथ्य आहार शरीर व मन को बल प्रदान करता है। शरीर का वर्ण यथावत् बनाये रखता है। शरीर की इन्द्रियों (आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि) की शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है। जैसे कहा गया है कि –

'वर्णः प्रसादः सौस्वर्य जीवितं प्रतिभा सुखम्।
तुष्टिः पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्।।

इसलिये अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित बताया गया है।

पथ्य अर्थात् हितकारी। व्यक्ति की अपनी प्रकृति के लिये हितकारी जानने के बाद भी अगर **मात्रा** उस आहार द्रव्य की अधिक हो जाए या **ऋतु (काल) विपरीत** हो तो वह आहार के योग्य गुणों से उसे युक्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य दुर्बल है, शारीरिक श्रम कम करते है, स्वस्थ नहीं रहते, कोमल प्रकृति के है, सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहें है ऐसे ही मनुष्यों के लिये आहार की गुरुता या लघुता का विचार किया जाना चाहिए। गुरु अर्थात् **'तत्र यच्चिरेण पच्यते तद् गुरु गुणम्।'** जो आहार देर से पचता है उसे गुरु कहते है। और **'यच्छीघ्रं तल्लघुगुणम्।'** जो आहार शीघ्रता से पचता है वह लघु गुण को बताता है। जैसे आयुर्वेद में मूंग को लघु तथा उड़द को गुरु बताया गया है। पिट्ठी से निर्मित पदार्थ, चावल, चेवडा आदि पचने में देर लगाते है अतः **भोजन के पश्चात् नहीं खाना** चाहिए। दूध की मलाई, छेना, मछली, दही, उड़द, जई (वंजे) का **सेवन लगातार नहीं** करना चाहिए।

साठी का चावल, शालि धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ, आकाशीय जल, दूध, जांगल मांस व शहद आदि का नित्य सेवन आयुर्वेद में हितकर माना है।

साठी का चावल, शालि धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ, आकाशीय जल, दूध, जांगल मांस व शहद आदि का **नित्य सेवन आयुर्वेद में हितकर माना** है। इसलिये ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करते रहना चाहिये, जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे तथा जो रोग उत्पन्न नहीं हुए है उनकी उत्पत्ति न हो।

चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्याय 27 में कहा भी गया है कि–

'षट्त्रिंशतं सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः।
जीवत्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा संमतः सताम्।।'

अर्थात्– हितकारी भोजन करने वाले जितेन्द्रिय पुरुष सज्जनों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए रोग रहित होकर 36000 रात्रि (दिन) अर्थात् 100 वर्ष तक जीवित रहते है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

*संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो, हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–'**व्हाटसएप**'। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –*

आयुर्वेदिक दोहे

- दही मथें माखन मिले, केसर संग मिलाय,
  होठों पर लेपित करें, रंग गुलाबी आय..
- बहती यदि जो नाक हो, बहुत बुरा हो हाल,
  यूकेलिप्टिस तेल लें, सूंघें डाल रुमाल..
- अजवाइन को पीसिये, गाढ़ा लेप लगाय,
  चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जाय..
- अजवाइन को पीस लें , नीबू संग मिलाय,
  फोड़ा–फुंसी दूर हों, सभी बला टल जाय..
- अजवाइन–गुड़ खाइए, तभी बने कुछ काम,
  पित्त रोग में लाभ हो, पायेंगे आराम..
- ठण्ड लगे जब आपको, सर्दी से बेहाल,
  नीबू मधु के साथ में, अदरक पियें उबाल..
- अदरक का रस लीजिए. मधु लेवें समभाग,
  नियमित सेवन जब करें, सर्दी जाए भाग..
- रोटी मक्के की भली, खा लें यदि भरपूर,
  बेहतर लीवर आपका, टी.बी भी हो दूर..
- गाजर रस संग आँवला, बीस औ चालिस ग्राम,
  रक्तचाप हिरदय सही, पायें सब आराम..
- शहद आंवला जूस हो, मिश्री सब दस ग्राम,
  बीस ग्राम घी साथ में, यौवन स्थिर काम..
- चिंतित होता क्यों भला, देख बुढ़ापा रोय,
  चौलाई पालक भली, यौवन स्थिर होय..
- लाल टमाटर लीजिए, खीरा सहित सनेह,
  जूस करेला साथ हो, दूर रहे मधुमेह..
- प्रातः संध्या पीजिए, खाली पेट सनेह,
  जामुन–गुठली पीसिये, नहीं रहे मधुमेह..
- सात पत्र लें नीम के, खाली पेट चबाय,
  दूर करे मधुमेह को, सब कुछ मन को भाय..
- सात फूल ले लीजिए, सुन्दर सदाबहार,
  दूर करे मधुमेह को, जीवन में हो प्यार..
- तुलसीदल दस लीजिए, उठकर प्रातःकाल,
  सेहत सुधरे आपकी, तन–मन मालामाल..
- थोड़ा सा गुड़ लीजिए, दूर रहें सब रोग,
  अधिक कभी मत खाइए, चाहे मोहनभोग..
- अजवाइन और हींग लें, लहसुन तेल पकाय,
  मालिश जोड़ों की करें, दर्द दूर हो जाय..
- ऐलोवेरा–आँवला, करे खून में वृद्धि,
  उदर व्याधियाँ दूर हों,जीवन में हो सिद्धि..
- दस्त अगर आने लगें, चिंतित दीखे माथ,
  दालचीनि का पाउडर, लें पानी के साथ..
- मुँह में बदबू हो अगर, दालचीनि मुख डाल,
  बने सुगन्धित मुख, महक, दूर होय तत्काल..
- कंचन काया को कभी, पित्त अगर दे कष्ट,
  घृतकुमारि संग आँवला, करे उसे भी नष्ट..
- बीस मिली रस आँवला, पांच ग्राम मधु संग,
  सुबह शाम में चाटिये, बढ़े ज्योति सब दंग..
- बीस मिली रस आँवला, हल्दी हो एक ग्राम,
  सर्दी कफ तकलीफ में, फ़ौरन हो आराम..
- नीबू बेसन जल शहद, मिश्रित लेप लगाय,
  चेहरा सुन्दर तब बने, बेहतर यही उपाय..
- मधु का सेवन जो करे, सुख पावेगा सोय,
  कंठ सुरीला साथ में, वाणी मधुरिम होय..
- पीता थोड़ी छाछ जो, भोजन करके रोज,
  नहीं जरूरत वैद्य की, चेहरे पर हो ओज..
- ठण्ड अगर लग जाय जो नहीं बने कुछ काम,
  नियमित पी लें गुनगुना, पानी दे आराम..
- कफ से पीड़ित हो अगर, खाँसी बहुत सताय,
  अजवाइन की भाप लें, कफ तब बाहर आय..
- अजवाइन लें छाछ संग, मात्रा पाँच गिराम,
  कीट पेट के नष्ट हों, जल्दी हो आराम..
- छाछ हींग सेंधा नमक, दूर करे सब रोग,
  जीरा उसमें डालकर, पियें सदा यह भोग..।

सस्ता होम लोन लेना हुआ आसान

साल 2022 तक दो करोड़ घर बनाने के टारगेट को पूरा करने के लिए केंद सरकार ने एक और कदम उठाया है। होम लोन पर सब्सिडी देने के फैसले के बाद अब सरकार ने 231 बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को मंजूरी दी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सस्ता होम लोन मिल सके। सरकार ने छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए स्माल फाइनेंस बैंक तक को मंजूरी दे दी है, ताकि इन शहरों में रह रहे लोग भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का फायदा ले सकें।

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को लोन देने के लिए एनएचबी ने अब तक 174 बैंक और फाइनेंस कंपनियों को मंजूरी दे दी है, जबकि हडको अब तक 57 कंपनियों (कुल 231) को मंजूरी दे चुका है। इसी तरह एक जनवरी 2017 से एमआईजी कैटेगिरी को भी सीएलएसएस का लाभ देने की घोषणा के बाद एनएचबी 157 बैंकों और फाइनेंस कंपनियों और हडको 36 कंपनियों (कुल 193) को मंजूरी दे चुका है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगिरी में 19 सरकारी बैंक, 12 प्राइवेट बैंक, 37 रूरल बैंक, 17 कोऑपरेटिव बैंक के अलावा 76 हाउसिंग फाइनेंस, 6 स्मॉल फाइनेंस और 7 माइक्रो फाइनेंस इंस्टिटयूशन के नाम शामिल हैं। इसी तरह एमआईजी कैटेगिरी में 19 सरकारी बैंक, 12 प्राइवेट बैंक, 27 रूरल बैंक, 13 कोऑपरेटिव बैंक के अलावा 72 हाउसिंग फाइनेंस, 7 स्मॉल फाइनेंस बैंक और 7 माइक्रो फाइनेंस इंस्टिटयूशन शामिल हैं।

आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में 25 फीसदी इजाफा

वित्त वर्ष 2016–17 में आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने वालों की संख्या 25 फीसद बढ़कर 2.82 करोड़ तक पहुंच गई। आयकर विभाग का कहना है कि नोटबंदी के बाद ज्यादा लोग अब आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं जिससे इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। व्यक्तिगत लोगों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने का आंकड़ा 5 अगस्त तक बढ़कर 2.79 करोड़ पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में इस अवधि तक 2.22 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे। इस तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 25.3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी और स्वच्छ धन अभियान की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।

5000 रु. से ज्यादा जमा करने पर शुल्क

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहक अपनी ब्रांच से इतर कहीं भी अगर 5000 रुपए से ज्यादा नकद जमा करेंगे तो उन्हें शुल्क अदा करना होगा। फिर चाहे नॉन–बेस ब्रांच उसी शहर में

ही क्यों न हो, जहां खाताधारक का खाता खुला है। यह नियम सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान में पीएनबी के ग्राहकों को केवल शहर के भीतर नॉन–बेस ब्रांच में ही 25 हजार रुपए से ज्यादा नकद जमा करने पर शुल्क देना पड़ता है। नए नियम के तहत ग्राहकों को 5,000 रुपए से ऊपर नकदी जमा करने पर एक रुपए प्रति हजार की दर से भुगतान करना होगा।

दूसरे शहर या राज्य में स्थित शाखा में एक सितंबर से 5000 रुपए तक नकद जमा फ्री होगा। अभी यह सीमा 25 हजार रुपए है। ऐसी शाखाओं में 5000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर बैंक दो रुपए प्रति हजार की दर से शुल्क वसूलेगा। बैंक ने चेक वापसी शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है।

एक करोड़ से ज्यादा की रकम के पहले चेक के लिए चेक वापसी शुल्क बढ़ाकर दो हजार किया गया है। इसके बाद बाउंस होने पर यह शुल्क ढाई हजार होगा। अभी एक करोड़ से ज्यादा के चेक वापसी पर शुल्क पहले चेक के लिए एक हजार और इसके बाद डेढ़ हजार रुपए है।

घर में फ्रिज, एसी और कार, तो नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ

अगर आपके घर फ्रिज, एसी या कार है तो आपको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। शहरी क्षेत्रों में हर 10 में से छह घरों में यह पहचानने के लिए

मूल्यांकन किया जाएगा कि वे सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के हकदार हैं या नहीं। इसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में जिन परिवारों के पास 4 रूम्स का फ्लैट, चारपहिया वाहन या एयर कंडिशनर है वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की लिस्ट से स्वतः निकल जाएंगे। परिवारों का मूल्यांकन शून्य से 12 के पैमाने पर किया जाएगा। ये पैमाने आवासीय, सामाजिक और व्यावसायिक अभाव होंगे।

धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम

16 जून से केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना रिवाइज करने का फैसला किया था। 16 जून से 17 जुलाई 2017 तक दोनों वस्तुओं के दामों में इजाफा नहीं हुआ, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इन 30 दिनों में पूरे देश में पेट्रोल के दामों में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम मुंबई में गिरे हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 4.99 रुपये प्रति लीटर कम हुए हैं। इसके बाद चेन्नई में 3.36 रू., दिल्ली में 2.80 रू. और कोलकाता में 1.97 रू.प्रति लीटर की कमी आई है। वहीं डीजल के दामों में तीन रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। मुंबई में बीते दिनों में डीजल के दाम

3.20 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं। वहीं चेन्नई में 1.30 पैसे, नई दिल्ली में 1.01 पैसे और कोलकाता में 0.61 पैसे प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई है।

जून 16 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के प्राइस में 1.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 1.24 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। इसके बाद से तेल कंपनियां रोजाना 1 से 20 पैसे प्रति लीटर की कमी कर रही थी।

दिल्ली-मुंबई का सफर अब 13 घंटे में

अब दिल्ली से मुंबई का रेल से सफर 13 घंटे में पूरा होगा। इसके लिए रेलवे ने पूरे रूट पर अपना ट्रायल शुरू कर दिया है। रेलवे के इस ट्रायल में ट्रेन राजधानी के तय समय से कम दूरी में पहुंची है। इस ट्रेन ने पूरा सफर तय करने में राजधानी एक्सप्रेस के मुकाबले 3 घंटे कम लगाए थे। इस ट्रायल से रेलवे को भरोसा है कि रात में सफर करके अगले दिन सुबह दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकेगा। अभी दिल्ली से ट्रेन शाम को 4.30 बजे रवाना होती है और अगले दिन सुबह 8.30 पर मुंबई पहुंचती है। पूरे सफर के दौरान यह कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत स्टेशन पर रुकती है। फिलहाल जो 24 कोच वाली ट्रेन इस रुट पर चल रही है उसकी स्पीड 130 किलोमीटर है। मोड़ पर ट्रेन की रफ्तार को 90 किलोमीटर पर रखा जाता है। 1386 किलोमीटर का सफर ट्रेन 15.35 घंटे में पूरा करती है।

एयर इंडिया ने बंद किया मांसाहारी भोजन

एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों की केवल इकोनोमी श्रेणी में ही मांसाहारी भोजन बंद किया गया है और इससे आठ से 10 करोड़ रूपए तक बचत होने का अनुमान है। नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मांसाहारी भोजन एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों की केवल इकोनोमी श्रेणी में ही बंद किया गया है। सिन्हा ने कहा कि इसकी शुरूआत लागत में कमी लाने, खर्च को कम करने, सेवा में सुधार तथा भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए भी की गयी है।

बीजों के दाम 10 प्रतिशत कम

प्रोडक्शन की ऊंची लागत से जूझ रहे किसानों को सीड (बीज) इंडस्ट्री ने बड़ी राहत दी है। इंडस्ट्री ने कॉटन को छोड़कर सभी बीजों की कीमतों में 10 फीसदी तक कमी का फैसला किया है, जो आगामी 2017-18 खरीफ सीजन के लिए 19 जून से लागू होंगी। इसके अलावा सरकार भी जल्द दालों के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल

तक की बढ़ोत्तरी कर सकती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने सीड इंडस्ट्री से स्वेच्छा से बीजों की कीमतों में कमी का आह्वान किया था।

इससे पहले सीएसीपी (कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस) ने खरीफ फसलों की एमएसपी की सिफारिश सरकार को सौंप दी है। सीएएसपी कुल 22 फसलों के एमएसपी की सिफारिश सरकार को करती है। पिछले साल भी सरकार ने 450 रुपए तक तिलहन और दलहन का एमएसपी बढ़ाया था। लेकिन, इसके बाद किसानों के साथ मंडियों में जो खेल हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। 5225 रुपए प्रति क्विंटल वाली मूंग दाल को किसान महज 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचने को मजबूर हुए। हालात यह हैं कि मौजूदा समय में भी किसान अपनी फसल को एमएसपी से नीचे बेचने को मजबूर हैं। 15 जून 2017 को एगमार्क. नेट (सरकारी मार्केट प्राइसमॉनेटरेरिंग वेबसाइट) के अनुसार मध्य प्रदेश में किसानों ने गेहूं, तुअर, सोयबीन, मसूर, सरसों और जौ आदि फसलों को निर्धारित एमएसपी से नीचे बेचा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की तमाम मंडियों में किसानों ने दलहन और तिलहन फसलों को एमएसपी से नीचे बेचने को मजबूर हुए। ऐसे में सरकार के एमएसपी बढ़ाए जाने का किसानों को किस तरह फायदा मिलेगा यह बात इसी आंकडों से समझी जा सकती है

प्रमुख फसलों का मौजूदा एमएसपी

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	पुराना एमएसपी
तुअर	5,050
मूंग	5,225
उड़द	5,000
मूंगफली	4,220
सोयाबीन	2,770
सूरजमुखी बीज	3,950
धान	1,470 व 1,520 (ग्रेड ए)
मक्का	1,365

इससे पहले कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा था कि सरकार कर्ज माफी के बजाय किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार चाहती है कि कृषि लागत मूल्य कम किया जाए ताकि किसान अच्छी आमदनी से जरूरत को लिया हुआ कर्ज आसानी से चुका सकें। इसके लिए शुरूआती तौर पर बीज बनाने वाली कंपनियों से बातचीत कर बीजों के दाम घटाने को कहा जाएगा। इससे पहले सरकार ने साफ कर दिया था कि वह कर्ज माफी में राज्य सरकारों को कोई सपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि, सरकार का जोर आमदनी बढ़ाने पर है।

खरीफ की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान

देश में चालू खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन का आंकड़ा बीते साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। केंद्रीय कृषि सचिव शोभना पटनायक ने एक साक्षात्कार में यह अनुमान जाहिर किया। पिछले 2016–17 के खरीफ सत्र में 13.80 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह खेती के रकबे का बढ़ना और लगातार दूसरे साल बेहतर मानसून रहना है। अब तक धान, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना और जूट जैसी खरीफ फसलों की 80 फीसद से भी ज्यादा बुवाई हो चुकी है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बुवाई का काम अगले माह तक जारी रहेगा। देश भर में बाढ़ के कारण करीब 19 लाख हेक्टेयर फसल का रकबा प्रभावित हुआ है। पानी घटने के बाद किसानों के अन्य खरीफ फसलों को अपनाने की संभावना है। कुछ राज्यों में बाढ़ और कर्नाटक के बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात थे। इन सबके बाद भी अब तक खरीफ फसलों के रकबे में करीब तीन फीसद का इजाफा हुआ है।

कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते तक किसानों ने 878.23 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी कर ली थी। यह रकबा पिछले साल की समान अवधि में 855.85 लाख हेक्टेयर था। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दलहन फसलों के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि खरीफ की तिलहन फसलों के बुवाई रकबे में कमी आई है। इस साल यह 148.88 लाख हेक्टेयर रह गया। बीते साल खरीफ सत्र में इन फसलों का रकबा 165.49 लाख हेक्टेयर था।

अब वापिस आ सकता है काला धन

स्विट्जरलैंड सरकार ने अपने राजकीय गजट में एक विस्तृत अधिसूचना में तथ्य प्रकाशित किए हैं। सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ वित्तीय खातों की जानकारी का स्वतः साझाकरण करने के समझौता कर रही है। उसने अन्य वित्तीय केंद्र लिंचेस्टाइन और बहमास का उदाहरण दिया है जो इसी तरह का समझौता करेंगे। सरकार ने यह जानकारी जर्मन भाषा में प्रकाशित की है और साथ ही भारतीय बाजार में अपनी संभावनाएं

तलाशने के बारे में भी उसने इसमें बात की है जिसमें पुनर्बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र शामिल है। उल्लेखलीय है कि जून में स्विस फेडरल काउंसिल ने भारत के साथ इस समझौते की पुष्टि की थी। यह काउंसिल यूरोपीय देशों की शीर्ष गर्विनंग इकाई है।

स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था शुरू करने की तारीख की सूचना भारत को जल्द ही देगी। परिषद द्वारा इस संबंध में स्वीकृत प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार, इसके लिए वहां अब कोई जनमत संग्रह नहीं कराया जाना है। इसलिए इसे लागू करने में देरी की आशंका नहीं है। कालेधन का मुद्दा भारत में सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा है। लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि बहुत से भारतीयों ने अपना काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक–खातों में जमा कर रखा है। भारत विदेशी सरकारों, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ अपने देश के नागरिकों के बैंकिंग सौदों के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर जोरदार प्रयास करता आ रहा है।

स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अब इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का अनुपालन करना होगा। टैक्स संबंधी सूचनाओं के स्वतः आदान–प्रदान (ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फर्मेशन) पर वैश्विक संधि को मंजूरी के प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद (मंत्रिमंडल) की मुहर लग गई है। स्विट्जरलैंड सरकार ने इस व्यवस्था को साल 2018 से संबंधित सूचनाओं के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है यानी आंकड़ों के आदान प्रदान की शुरूआत 2019 में होगी।

जीएसटी रेट में हो सकता है बदलाव

जुलाई माह में लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की दरों में बदलाव हो सकता है। वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी की दरों को एक समान करने की संभावना भी बरकरार है। सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी को जम्मू–कश्मीर तक बढ़ाने से जुड़े बिलों पर बहस के दौरान अरुण जेटली ने यह बात कही। यह दोनों बिल लोकसभा से पास हो गए। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट है कि सरकार 12 और 18 को एक में मिला दे। जेटली ने यह भी कहा कि उनपर जीएसटी में बदलाव करने का दबाव था। लोग कह रहे थे इसमें खामी है मगर उन्होंने पाया कि इसका ढांचा सही है। जीएसटी में कई दरों को लेकर हो रही आलोचनाओं पर वित्तमंत्री ने कहा कि भारत जैसे देश में कोई एक स्लैब नहीं हो सकता, जहां कि बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि बीएमडब्लू कार और चप्पल पर समान टैक्स नहीं हो सकता।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन बिलों के पास होने से देश के अन्य हिस्सों के साथ इस राज्य की आर्थिक एकजुटता सुनिश्चित हो सकेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू–कश्मीर को मिला विशेष राज्य के तमगे का मतलब उसके लिए आर्थिक रुकावट पैदा करना नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी राज्य और यहां के व्यापारियों के हित के लिए है। लोकसभा ने इन दोनों बिलों को ध्वनिमत से पास किया गया। दोनों बिलों को जरूरी औपचारिक संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। इसमें जम्मू–कश्मीर को दी गई छूट को अलग रखा गया है। जीएसटी के जरिए जम्मू–कश्मीर भी देश के कारोबार से जुड़ गया है।

स्मार्टफोन मार्केट के आधे हिस्से पर चीन का कब्जा

साल 2017 की दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन की वैश्विक बिक्री में सालाना आधार पर 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों ने एपल की बाजार हिस्सेदारी में सेंध लगाते हुए 48 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल कर ली। मार्केट रिसर्च कंपनी काउंटरप्वाइंट रिसर्च की जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की स्मार्टफोन कंपनियों ने भारत, दक्षिण एशिया और अफ्रीका समेत दुनिया भर में 48 फीसदी की बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसमें श्याओमी की बिक्री में 60 फीसदी, वीवो की 45 फीसदी, ओप्पो की 33 फीसदी और हुआवे की बिक्री में सालाना आधार पर 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये स्थिति तब है जब एप्पल ने अपने आईफोन के लिए ओएलईडी पैनल उत्पादन के लिए एलजी में 2.70 अरब डॉलर का निवेश किया है। ❑❑

जिला सम्मेलन, फरीदाबाद (हरियाणा)

6 अगस्त 2017

स्वदेशी जागरण मंच, फरीदाबाद द्वारा राजस्थान सेवा सदन में 6 अगस्त 2017 को जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्यकर्त्ता व जन सामान्य को चीन से मिल रही दोहरी चुनौती के बारे में तत्थों से पूर्णतया अवगत कराना था, ताकि बेहतर ढ़ंग से चीन का मुकाबला किया जा सके। इस अवसर पर **'राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान'** प्रमुख श्री सतीश कुमार के विभिन्न भाषणों से संकलित **"चीन की चुनौती व हमारा कर्तव्य"** नामक पुस्तक का विमेचन भी किया गया।

मुख्य वक्ता श्री सतीश कुमार *(राष्ट्रीय प्रमुख–राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान, अखिल भारतीय सह–विचार मंडल प्रमुख एवं त्री क्षेत्र (उत्तर क्षेत्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश) संगठक)* ने उपस्थित कार्यकर्ताओं व जनसमूह को संबोधित करते हुये कहा कि चीनी माल की वजह से भारत में उद्योग–धंधे बंद हो रहे हैं, जबकि चीन अपने यहां सब्सिडी देकर, किसानों और मजदूरों का शोषण करके सस्ता माल भारत भेज रहा है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग कर रहा है। साथ ही भारत को न्यूक्लियर एनर्जी सप्लायर ग्रुप (एन.एस.जी.) में शामिल करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी सामान के बहिष्कार को राष्ट्रीय दायित्व करार दिया है और लोगों से अभियान के दौरान अपील की जा रही है कि वे चीनी सामान का बहिष्कार करके अपने दायित्व को पूरा करें। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार पर चीन के हावी होने से 3425 अरब रुपए का व्यापार घाटा भारत को प्रतिवर्ष हो रहा है। साथ ही दलील दी कि भारत के कुल विदेशी मुद्रा घाटे का 41 फीसदी चीन की वजह से हो रहा है।

मुख्य अतिथि नगर निगम फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि राष्ट्रभक्ति से बडा कोई धर्म नहीं है। एनजीएफ शिक्षण संस्थान समूह के चेयर पर्सन श्री अश्विनी प्रभाकर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि वह भी अपने विद्यार्थियों में स्वदेशी की मंत्र फूकेंगे।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय सह संयोजक श्री सतेंद्र सौरोत ने कहा कि वह फरीदाबाद में अब तक लगभग 30 हजार विद्यार्थियों, हजारों प्रबुद्ध नागरिकों, वकीलों, अध्यापकों, किसान नेताओं, व्यापारियों, समाजिक–धार्मिक नेताओं आदि से मिलकर विदेशी वस्तुओं, विशेषतः चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर, समर्थन प्राप्त कर चुके हैं। जबकि पूरे हरियाणा में लगभग साढ़े नौ लाख लोगों से प्रत्यक्ष समर्थन मिल चुका है। अगामी महीनों में यह आंकड़ा करोडों में पहुंचाने का लक्ष्य है।

इस अवसर पर राकेश त्यागी, कर्नल वी.एस. सौरोत, देशबन्धु गुप्ता, रविन्द्र मंगला, पार्षद दीपक चौधरी, वरिष्ठ सीए संजय अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ, सर्व इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष विदुर सोगी, प्रोफेसर रवि प्रकाश, वरिष्ठ प्राध्यापक रविन्द्र मनचंदा, कुलबीर यादव, महाबीर यादव, वीरेश सांडिल्य, सीमा भारद्वाज, कमलादेवी, बिमला देवी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक अजीत तेवतिया, फरीदाबाद के जिला संयोजक कुणाल राज गोयल, अमरदीप सिंह, डॉ कृष्णकांत उपाध्याय, पलवल के जिला संयोजक अमरसिंह सौरोत, फरीदाबाद पश्चिम के जिला संयोजक पारस अग्रवाल व उनके सहयोगी संजय मैथिल, कौशल किशोर आदि की सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका रही। सभागार को चीन विरोधी नारों (जैसे– **'चीनी वस्तुएं त्यागकर बोलो वन्देमातरम'** आदि) से सुसज्जित किया।

संचालन डॉ. के.के. उपाध्याय व अमरदीप सिंह ने किया, धन्यवाद जिला संयोजक कुणाल गोयल ने किया।❑❑